10·54

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शिक्षा बचाओ आन्दोलन

प्रकाशन क्रमांक - 48

अगस्त 2009

- क्या आप चाहते हैं कि
- अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, राष्ट्र विभाजन का षड्यंत्र-राजस्थान पत्रिका 24-04-2009
- यौन शिक्षा के बदले चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास की शिक्षा
- भारत के महान वैज्ञानिक
- शेक्सपियर के वैभव के पीछे- जातीय वैमनस्य के बीज
- शिक्षा का अधिकार 2009
- एनसीईआरटी की पुस्तकों में इतिहास के साथ खिलवाड़
- Vedic Mathmatics- Dr. Nariender Puri
- Sh Madan Lal Dhingra's Case & M.K. Gandhi
- School or shop? -The Tribune 11/08/09
- Secularism -Dr. A.B.L. Gupta
- Teach Them Young -By V.S. Chaudhari (Retd. I.A.S.)
- De-Stressing Students -The Tribune, 11/08/09
- Dont't allow foreign universities in a hurry -Joshi
- गतिविधियाँ

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास

सरस्वती बाल मंदिर, जी ब्लाक, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028

फोन :- 29841216, 65794966, 9811126445, 9212385844

E-mail : dina_nathbatra@hotmail.com • atulabvp@gmail.com

Website : www.shikshabachaoandolan.org

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय सूची

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाठकों के नाम पत्र

परम बन्धुवर

भारत वन्दे!

प्रति दो मास में एक पुस्तिका प्रकाशित हो रही है। सुधी पाठकों के लिए अब **क्रमांक 48** आप के अध्ययन के लिए सेवा में प्रेषित है

इस पुस्तिका में साम्य सामयिक सामग्री दी गई है। विशेष लेख ऐसे हैं जो आन्दोलित करते हैं और विचारार्थ चुनौतिक के रूप में प्रश्न चिन्ह बन कर खड़े हैं। क्या यह खड़े रहेंगे? हम पढ़ेंगे, समझेंगे तथा क्रिया के लिए दृढ़ संकल्पी बन शिक्षा बचाओ आन्दोलन को सृजनात्मक सहयोग प्रदान करेंगे।

भारत के मुख्य न्यायधीश बालाशंकरन ने भारतीय भाषाओं पर कटाक्ष कर एक ओर संविधान की धारा 354 का उल्लंघन किया है वहीं दूसरी ओर शिक्षा में व्यापारीकरण को परोक्ष रूप से प्रोत्साहित किया है। देशभर से माननीय मुख्यन्यायधीश को रोषपत्र भेजे जा रहे हैं। गुजरात के हिन्दी प्रेमी डा. हर्षद पंडित ने हिन्दी को प्रतिष्ठित स्थान दिलाने के लिए एक लाख लघुपुस्तिका छपवाई है और वह निःशुल्क वितरित कर रहे हैं, इसके लिए उनको साधुवाद। उसी पुस्तिका के आधार पर एक लेख इस पुस्तिका में है "क्या आप चाहते हैं कि" अवश्य पढ़िये।

राजस्थान पत्रिका में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को **अल्पसंख्यक तुष्टीकरण-राष्ट्र विभाजन** का षडयंत्र इस शीर्षक से छापा है। इस महत्वपूर्ण विषय को पत्रिका से साभार से यहां प्रस्तुत किया है।

राज्यसभा की याचिका समिति के सम्मुख देशभर के विद्वानों, आचार्यों तथा विद्यार्थियों ने अपना पक्ष इतनी प्रबलता से रखा कि समिति ने कहा है **"कि यौन शिक्षा के बदले चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास की शिक्षा"** शिक्षण संस्थाओं में लागू होगी। यह हमारे आन्दोलन की बहुत बड़ी जीत है। आप सब सहभागियों को बधाई। भाई अतुल कोठारी का लेख इस विषय को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत के महानवैज्ञानिक संकलित सामग्री है। यह हमारा गौरव गान है, आईए मिल कर गाएं।

मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल की ओर से शिक्षा का अधिकार 2009 संसद में पेश हुआ दोनों सदनों में यह पारित हो गया है। राष्ट्रपति जी की स्वीकृत शेष है। बिल के पक्ष तथा विपक्ष में श्री दीनानाथ बत्रा का समीक्षात्मक लेख भी पढ़ने के लिए अच्छा है।

एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तकों के लिए हमने बहुत संघर्ष किया – न्यायालयों के आदेश से आपत्तिजनक अंश निकाल दिए गए परन्तु फिर से नई पुस्तकों में अपमानित करने वाली ऐतिहासिक विकृतियाँ आई हैं। डा. सतीश मित्तल महान इतिहासकार ने पुस्तकों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर हमे जानकारी दी है। पुनः संघर्ष के लिए तैयार रहिए।

श्री बी.एल. गुप्ता का धर्मनिरपेक्षता पर लेख अत्यंत ही शैक्षिक, यथार्त तथा वस्तुस्थिति परक है। इस शब्द ने देश की बहुत बड़ी हानि की है जितनी जल्दी इस शब्द से हम छुटकारा पा सकते हैं उतना ही अच्छा है।

डॉ. नरेन्द्र पुरी का वैदिक गणित विषय पर लेख प्रेरणादायक है। यह विषय अब विश्व का तथा कम्पयूटर की भाषा का विषय बनने जा रहा है। संसार में इस विषय के माध्यम से होने वाली क्रांति की प्रतीक्षा कीजिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने संसद में शिक्षा मंत्री को आह्वान किया है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में मत आने दीजिए, विश्वविद्यालय के साथ विदेशी संस्कृति तथा पाश्चात्यीकरण का भी आगमन होगा। यह हमारी स्वतंत्रता, सुतन्त्रता तथा स्वदेशी भाव पर चोट होगी। हम सबको मिलकर विरोध करना होगा।

धन्यवाद सहित,

शुभाकांक्षी

दीनानाथ बत्रा

अध्यक्ष

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्या आप चाहते हैं कि.....

- आपका बालक श्रेष्ठ मनुष्य बने? - **डॉ. हर्षद पंडित**
- आपका बालक पढ़ाई में खूब आगे बढ़े, डॉक्टर, इन्जीनीयर या वैज्ञानिक बने?
- आपका बालक संवेदनशील, समाजप्रेमी बने तो मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा ही **"गुरुचाबी"** है।
- आपको भी इस सहित्य का वितरण कर के इस महायज्ञ में सहभागी होने का निमंत्रण है।
- "मै आज वैज्ञानिक बन सका हूँ क्योंकि मैं मेरी मातृभाषा में पढ़ा हूँ"। **-डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम (पूर्व राष्ट्रपति)**
- "बालक के देह के विकास के लिए माँ का दूध जैसे स्वाभाविक है उसी प्रकार उसके मस्तिष्क के विकास के लिए मातृभाषा से अलग भाषा पढ़ाना वह मातृभाषा के सामने का अपराध है। विकास का आरंभ मातृभषा के संगीन खड़ग पर से ही हो ऐसा स्पष्ट हम देख सकें ऐसी खुल्ली बात केवल हिन्दुस्तान जैस दुर्भागी देश में ही सिद्ध करनी पड़ती है।" - **गांधी जी**
- "शिक्षण को यदि सार्वजनिक बनाना हो तो वह मातृभाषा में ही देना चाहिए अन्यथा समाज में भेदाभेद की दिवार खड़ी होगी।"

  - विनोबा भावे
- "संस्कार-संस्कृति का पतन उस देश की भाषा के पतन से होता है।"

  - गुणवंत शाह

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्री जगदीश चन्द्र बोस महान वैज्ञानिक कैसे बनें?

भगवानचन्द्र बसु ब्रिटिश राज में डेप्युटी मेजिस्ट्रट थे। उनके पुत्र जगदीश की आयु स्कूल में भेजने जितनी हुई। उस समय अंग्रेजी राज था, अंग्रेजी स्कूलों का प्रभाव भी फैला हुआ था, पर भगवानचन्द्र बसुने जगदीश के लिए एक बंगाली माध्यम की शाला पंसद की। लोगों ने उनसे पूछा, ''सरकारी नौकर होते हुए, नायब जिला मजिस्ट्रेट होते हुए भी आप अपने बालक को बंगाली शाला में भेज रहे हो''। भगवानचन्द्र बसु ने उत्तर दिया ''अंग्रेज़ी पढ़ने से पहले बालक को मातृभाषा बराबर सीख लेनी चाहिए। जिससे अंग्रेज़ी माध्यम के झूठे गर्व के कारण वह अन्यों से अलग न रह जाए''। यह बात है हमारे महान वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोस की। सन् 1914 में एक सम्मेलन में खुद जगदीश चन्द्र बोस ने कहा था कि ''शाला में एक मुस्लिंम चपरासी के लड़के और एक मछवारे के लड़के के बीच में मेरी बैठक थी। उनके मुँह से पशु, पक्षी, बनस्पति, नदियाँ, आदि की बातें सुनीं थी। शायद प्रकृति के रहस्यों की खोज की प्रेरणा मुझे उनसे ही मिली थी''। **''मातृभाषा की बुनियाद मजबूत होगी तो किसी भी भाषा का ज्ञान सहजता से मिल जाएगा।'' ''बालक का सहज और स्वाभाविक विकास मातृभाषा के वातावरण में ही होता है।''**

- **''अपने दिखावे के लिए बच्चे को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाने की आपकी इच्छा उसको बाल मजदूर बना देगी।''**
- **'अंग्रेज़ी को एक विषय के रूप में पढ़ना चाहिए, माध्यम के रूप में नहीं।''**
- **''बालक को उत्तम शिक्षा किस भाषा में ? जिस भाषा में उसे सपने आते हों उस भाषा में।''**
- **''याद रहे.....प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में ही हो।''**

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज्यसभा की याचिका समिति का सर्वसम्मत सुझाव

यौन शिक्षा के बदले 'चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास की शिक्षा' दी जाए

दो वर्ष पूर्व देश की शिक्षा में केन्द्र सरकार के द्वारा एक नया पाठ्क्रम यौन शिक्षा के नाम से लाने का प्रयास किया गया था। इसके तहत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या में देश की संस्कृति, संविधान के विरुद्ध अनेक बातें थीं। इसके विरूद्ध में शिक्षा बचाओ आन्दोलन के नेतृत्व में देश की अनेक सामाजिक, शैक्षिक, (अ.भा.वि.प. सहित) संस्थाओं ने देशव्यापी आंदोलन चलाया, इसके परिणामस्वरूप 11 राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के निर्णय के विरूद्ध सेक्स एज्युकेशन पर रोक लगा दी थी। समग्र देश में इस शिक्षा पर रोक लगाई जाए इस मांग के साथ दिल्ली की आशा शर्मा एवं मुंबई की प्रतिभा नैथानी ने राज्यसभा को 17 मई 2007 को एक याचिका प्रस्तुत की। माननीय सभापति ने 9 अगस्त को याचिका को गृहित कर लिया। 16 अगस्त को राज्यसभा में प्रतिवेदन किया, जिसके पश्चात इसे समिति को जांच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए भेजा गया।

इसके बाद याचिका समिति (पेटिशन कमेटी) ने कार्य शुरू करके दिल्ली, कोलकता, मुंबई, तिरुअन्तपुरम, हैदराबाद, बंगलोर एवं मुंबई जैसे देश के सात मुख्य केंद्रों पर सुनवाई की, जिसमें समिति को 40 हजार से अधिक आवेदन एवं पत्र प्राप्त हुए। शिक्षा बचाओ आन्दोलन ने भी देश भर से 4 लाख 15 हजार हस्ताक्षरों के साथ समिति को ज्ञापन दिया था। समिति के द्वारा आवेदन पत्रों के अध्ययन से मालूम हुआ कि इसमें से अधिकतर यौन शिक्षा के विरूद्ध थे। याचिका समिति ने लगभग 19 मास कार्य करते हुए 2 अप्रैल 2009 को राज्यसभा के सभापति एवं देश की उपराष्ट्रपति को 135 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी मुख्य बातें निम्न हैं।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अवलोकन / सिफारिशें

1. समिति ने यह पाया कि 'किशोर शिक्षा' के नाम भारत सरकार की अनेक एजेंसियों ने विद्यालयी पाठ्यक्रम में एक ऐसा पाठ्यक्रम शामिल करने की कोशिश की थी, जो अश्लील सामग्री से विद्यार्थियों का परिचय कराकर उनके अपरिपक्व और नाजुक मस्तिष्क को विकृत कर सकता है।

वास्तविकता यह थी कि किशोर शिक्षा कार्यक्रम की अध्ययन सामग्री अत्यंत आपत्तिजनक थी और इसे सिरे से ही नकार दिया जाना था। समिति के अनुसार, किशोर शिक्षा कार्यक्रम (एईपी) चालाकी से उपयोग की गई सूक्ति है, जिसका वास्तविक उद्देश्य स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देने और स्वच्छन्द संभोग को बढ़ावा देना था।

यह नोट करना व्यंग्यात्मक है कि एचआईवी/एड्स और इसकी रोकथाम के बारे में सूचना के प्रसार तथा कंडोम के इस्तेमाल द्वारा सुरक्षित यौन संबंध का प्रचार किशोर शिक्षा कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं है, जो 14 से 18 वर्ष के बीच के स्कूली बच्चों के लक्षित समूह के लिए है।

2. समिति के लिए यह जिज्ञासा का विषय भी है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) पूरी प्रक्रिया में इतने सक्रिय रूप से क्यों शामिल था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा निभाई गई भूमिका पर अपनी मौन स्वीकृति क्यों जारी रखी।

3. दूसरा क्षुब्ध करने वाला पहलू यह रहा कि कार्यक्रम को बनाने और लागू करने में राज्य सरकारों और अन्य हितार्थियों के साथ पर्याप्त विचार-विर्मश की कमी रही। 'शिक्षा समवर्ती' सूची में होने के नाते यह वांछनीय था कि सभी राज्य सरकारों के विचारों को सुनिश्चित कर दिया जाना चाहिए था।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अभिभावकों को इस पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु से अंजान रखा गया, यह विषय कभी भी सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा नहीं रहा।

दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किये गए किशोर शिक्षा कार्यक्रम (एईपी) के चार ख़ंडों और युवा के खंडों की अश्लील प्रकृति की सामग्री का अवलोकन करना समिति के लिए वास्तव में असहज कार्य था।

समिति की सिफारिशें

1. विद्यालयों में कोई भी यौन-शिक्षा नहीं होनी चाहिए।

2. बच्चों को समझाया जाए कि विवाह-पूर्व कोई भी यौन-क्रिया नहीं करनी चाहिए, वह अनैतिक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है।

3. विज्ञान सम्मत स्वास्थ्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सामाजिक जागरूकता हेतु उचित एवं आयु विशिष्ट पाठ्यक्रम तैयार किया जाए।

4. अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी को विद्यालय के बच्चों के बीच फैलाने की आवश्यकता है। छात्रों को हमारी परिवार प्रणाली के मूल्यों तथा इसे संरक्षित रखने की आवश्यकता के बारे में भी सिखाया जाना चाहिए।

5. नए पाठ्यक्रम में हमारे महान् संतों, आध्यात्मिक नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय वीर पुरुषों के जीवन तथा सीख के संबंध में समुचित सामग्री शामिल की जानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे हमारे राष्ट्रीय आदर्शों और मूल्यों को पुनः ग्रहण कर सकें, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्रोत्रों से हो रहे सांस्कृतिक आक्रमण का प्रभाव भी बेअसर हो जाएगा।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

6. इस संदर्भ में समिति इस तथ्य पर जोर देना चाहेगी कि हमारे विद्यालय के पाठ्यक्रम हमारे समाज एवं संस्कृति की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करें। हमारे देश के सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार ऐसे हैं कि इसमें यौन शिक्षा को कोई स्थान नहीं है। भोजन, भय, लालच, मैथुन इत्यादि जैसी मूलभूत मानवीय प्रवृत्तियों के बारे में शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण शिक्षा का विषय होना चाहिए। परंतु वर्तमान शैक्षिक प्रणाली इन प्रवृत्तियों को उत्तेजित करने का काम करती है, जो समाज के लिए घातक है। 'प्रवृत्ति नियंत्रण' संबधी भारतीय शिक्षा पर ध्यान देना महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए आत्मसंयम की मर्यादा को शिक्षा में अच्छी तरह संस्थापित किया जाना है।

❖ शेष अध्यायों को अधिक व्यापक बनाया जाए तथा इन्हें नए नाम 'चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाए

❖ 'प्राकृतिक चिकित्सा' 'आयुर्वेद' 'यूनानी' एवं 'योग' को नए पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए।

❖ नए पाठ्यक्रम का अंतिम लक्ष्य बच्चों के संपूर्ण विकास पर ध्यान देना होना चाहिए।

आज हमारे विद्यालय के पाठ्यक्रमों में नैतिक मूल्यों के विषय को पुनः प्रारंभ करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज मानवता के नीति परक मूल्य में अपनी अधिकांश आस्था खोता सा प्रतीत होता है। भारतीय धर्मग्रंथों एवं काव्यों में इन मूल्यों पर हमेशा बल दिया गया है। लंबे समय से एक पारिवारिक उत्तरदायित्व के रूप में समझे जाने

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
वाले नैतिक मूल्य की शिक्षा को किसी भी शैक्षणिक संस्थान के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए। किसी समाज के मूल्यों को मजबूत बनाने का उत्तरदायित्व केवल व्यक्तिगत प्रयासों तक ही सीमित नहीं है, वरन् शिक्षकों को भी आवश्यकता की इस घड़ी में अवश्य ही परामर्शदाता की भूमिका अपनानी चाहिए और एक बेहतर विश्व की ओर अग्रसर होने के लिए परिवर्तन लाना चाहिए-एक ऐसा विश्व जो हमारे ईर्द-गिर्द के लोगों के निस्वार्थ भाव से ओत-प्रोत हो। अतः अब यह महत्वपूर्ण हो गया है कि विद्यालय तथा महाविद्यालयों के सभी विषयों के शिक्षक एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दें।

समिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय (विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग) से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों / शिक्षा सचिवों को मौजूदा किशोर शिक्षा कार्यक्रम की अध्ययन सामग्री को यदि कोई अब भी पढ़ाई जा रही हो, को सभी राज्य संचालित अथावा सी.बी.एस.ई. संबद्ध विद्यालयों से वापस लेने का परामर्श जारी करने की अपिल करती है। राज्यसभा की याचिका समिति जिसमें कई पक्षों के सांसद थे, ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट तैयार करके राज्यसभा में प्रस्तुत किया है, वह तुरंत क्रियान्वित हो इस हेतु देशव्यापी प्रयास करके केंद्र सरकार पर दबाव बनाने से इस रिपोर्ट को क्रियान्वित किया जा सकेगा।

- **अतुल कोठारी**

(सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास)

सम्पर्क सूत्र : 9212385844

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत के महान वैज्ञनिक

1. भारद्वाज - वैदिक ऋषि जिन्होंने सर्वप्रथम विमान विद्या विषयक ग्रन्थ का निर्माण कियां। वह एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य भी थे

2. कपिल - सांख्य दर्शन के प्रवर्तक मुनि, जिनके अनुसार चेतन पुरुष और तीन गुणों से युक्त प्रकृति ही सृष्टि के मूल कारण है।

3. कणाद - वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक ऋषि, जिनका परमाणु प्रसिद्ध है।

4. सुश्रुत - शल्य चिकित्सा के जनक। उन्होंने त्वाचारोपण (पलास्टिक सर्जरी) और मोतियाबिंद की शल्य क्रिया का भी विकास किया।

5. चरक - काय चिकित्सा के मूल ग्रंथ चरक संहिता के रचयिता, जिसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है।

6. भास्कराचार्य द्वितीय - उन्होंने न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति की परिकल्पना की थी।' 'सिद्धान्त शिरोमणि' 'लीलावती, 'बीज गणित' आदि उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं।

7. वराह मिहिर - सम्राट विक्रमादित्य के राज ज्योतिषी और उनके नवरत्नों में से एक वराह मिहिर महान् ज्योतिषाचार्य थे। उनका "बृहत्संहिता" नामक ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है।

8. नागार्जुन - प्रसिद्ध रसायनशास्त्री और आयुर्वेदाचार्य प्रसिद्ध विद्वान् प्रो. पी.सी. राय ने अपने महान् ग्रन्थ 'दि हिन्दू कैमिस्ट्री' में उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

9. आर्यभट्ट प्रथम - 5वीं शती के महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य जिनका ग्रन्थ 'आर्यभट्टीयम्' लोकप्रसिद्ध है। 'पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है।' इस सिद्धान्त का विश्व में सर्वप्रथम उन्होंने ही प्रतिपादन किया था।

10. पंतजलि - 'योग सूत्र' के रचयिता। विश्व को योग का महान् योगदान आप ने दिया।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

11. ब्रह्मगुप्त - 'ब्रह्म स्फुट सिद्धान्त' के रचयिता, जो ज्योतिष और गणित का प्रामाणिक ग्रन्थ हैं। 'सूर्य सिद्धान्त के प्रतिपादक भी ब्रह्मगुप्त ही थे।

12. वाभट्ट - प्रसिद्ध आयुर्वेदचार्य, जिन्होंने 'अष्टांग हृदय' नामक ग्रंथ की रचना की।

13. भावमिश्रा - प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य, 'भाव प्रकाश' नामक ग्रंथ के रचयिता।

14. शार्गधर - प्रसिद्ध नाड़ी शास्त्र विशेषज्ञ। 'शार्गधर संहिता' के रचयिता।

15. जगदीश चन्द्र बोस - वनस्पतियों की सजीवता के सिद्धकर्ता तथा मार्कोनी से पूर्व ही 'बिना तार का तार' के आविष्कर्ता।

संकलनकर्ता

दीनानाथ बत्रा

भोपाल में वैदिक गणित की गोष्ठी

दिनांक 8, 9 अगस्त 2009 को भोपाल में अखिल भारतीय वैदिक गणित की एक परिणामकारी गोष्ठी हुई। गोष्ठी में इस विषय में 20 विद्वान उपस्थित हुए थे। अनेक प्रश्नों पर चर्चा हुई। वैदिक गणित का नामकरण तथा विधियाँ, विद्यालयीन तथा महाविद्यालयीन पाठ्यक्रम अपने देश तथा अन्य देशों में वैदिक गणित के प्रयोग के प्रकार से सम्बन्ध को प्रतियोगिता की दृष्टि से इस पर सारगर्भित चर्चा हुई। भोपाल में वैदिक गणित का शोध केंद्र स्थापित किया जए साथ ही विद्वानों की एक समिति भी गठित की गई जो इस कार्य के लिए अपनी योग्यता तथा प्रतिभा को समर्पित करेंगे। यह भी निर्णय हुआ की देश के पांच भागों में वैदिक गणित की गोष्ठियाँ भी आयोजित की जाएं। पूरे देश के विद्वानों को जोड़कर इस विषय को प्रभावी बनाया जायेगा।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेक्सपियर के वैभव के पीछे जातीय वैमनस्य के बीज

विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के बारे में इस देश में अंग्रेजी के पढ़ाए पाठ्यक्रमों के कारण हम कुछ न कुछ अवश्य जानते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कृति मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसका रचनाकाल 1596 माना जाता है। एक ऐसा नाटक है जिसमें तत्कालीन जातीय घृणा, द्वारागृह और यहुदियों की रूढ़िगत भद्दी छवि को इस प्रकार चित्रित किया गया है, जिस पर हमारे देश में तो कभी टिप्पणी नहीं हुई पर पश्चिम में अनेक विद्वान उस पर संकोच व असमंजस का सामना करते रहे हैं। शाईलॉक नामक यहूदी व्यवसायी के चरित्र का बहाना बनाकर पूरी जाति को उस समय का पश्चिम समाज कैसे देखता था, यह विचारणीय है। हमारे देश में जो व्यक्ति तुलसीदास व मनु को कोसने में ही अपने निष्पक्ष लेखन की इतिश्री कर लेते हैं उन्हें यह याद दिलाना आवश्यक है कि शेक्सपियर जैसे महान नाट्ककार ने भी एक ऐसे ओछे दुराग्रह को प्रतिबिम्बित किया है जहां किसी के धर्म, रंग या सामाजिक वर्ग या स्तर के अलग होने मात्र से घृणा स्वाभाविक मानी जाती थी। इस विषयपर तो कुछ अंग्रेज़ी साहित्यकारों व आलोचकों ने स्वयं कईबार लिखा है कि यदि 'मर्चेंट ऑफ वेनिस' जैसा नाटक आज के युग में लिखा गया होता तो इंग्लैंड में ही वर्तमान कानूनों के अंतर्गत जातीय वैमनस्य फैलाने व समरसता भंग करने के आरोप में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया होता और इसके लेखक को दण्डित किया जाता। उदाहरण के लिए यह कानून की दृष्टि में अपराध है कि किसी को वर्ग या नस्ल के आधार पर या कोई याहूदी या महिला है, इस आधार पर कोई नौकरी न दी जाए। यहूदियों के प्रति घृणा व विविधा के रूप में शाईलॉक नामक एक ऐसे पात्र का सृजन करना जिससे यहूदी चरित्र की दुष्ट व कलंकित छवि का प्रतीक बनाकर आज पूरा मुहावरा ही अंग्रेजी में प्रचलित है –'ए पाउन्ड आफ फ्लेश'। यहूदी व्यापारी शाईलॉक ने एक अनुबंध के अंतर्गत ईसाई पात्र एन्टोनियो द्वारा ऋण न चुकाए जाने पर उसका एक पाउंड मांस काटने की जिद करना और पोर्शिया के द्वारा एन्टोनियो के वकील के रूप में

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उसका पासा पलट देना नाटक का रोचक मोड़ है। पर इस प्रक्रिया में यहूदियों के प्रति उस समय समाज में कैसी घृणा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है जो वेनिस के तत्कालीन कानून के माध्यम ये दर्शकों को दिखाया गया है। इस मुकदमें के अन्त में वृद्ध, हताश व्यवासयी शाईलॉक अलग-थलग होकर मित्रहीन घृणा का पात्र बन गया और उसकी नियति को समाज के घृणित अलगावबाद की भावना में दिखाया गया है। वह समाज का बहरी व्यक्तिबन जाता है और वहां के नागरिक उसे ईसाईद्रोही, अपराधी, कुटिल, चालाक और सूदखोर की तरह देखते हैं। शाईलॉक के एक वार्तालाप में स्वयं शेक्सपियर ने एन्टोनियो के माध्यम से उसे 'डाग' और 'थर' (एक कटा कुत्ता) और घृणित' यहूदी तक कहा जिसके वस्त्रों पर विवरण से थूकता भी था। जब वेनिस के एक बड़े उद्योपति का यह हाल था तब हम कल्पना कर सकते हैं कि 500 वर्ष पहले तत्कालीन योरोपीय,ईसाई समाज में यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार हो सकता था। मजे की बात है कि स्वयं शाइलॉक एक संवाद में कहता है- क्या यहूदियों के आंख नही होती है? क्या उनके हाथ, शरीर के वैसे ही भागों या भावनाओां में फर्क होता है ? क्या यदि उन्हें -सुंई भोंके तो खून नहीं निकलेगा? क्या यदि हमे गुदगुदाएं तो हम नही हंसेगे? क्या फर्क है ईसाई और यहूदी में।

अंग्रेजी साहित्य और शेक्सपियर को न पढ़ने वाले भी उससे सम्मोहित रहते हैं, हमारा प्रबुद्ध वर्ग तो सबसे आगे रहता है। देश में छोटी कक्षा से लेकर कालेजों तक में शेक्सपियर के नाटक पाठ्यक्रम में रहते हैं पर उसकी जातीय घृणा की ये बातें हम विद्यार्थियों को कभी नहीं बताते हैं। आज स्वयं अंग्रेज लेखक इन बातों पर विस्तार से लिखते हैं और कुछ अमेरिकी विद्वान शेक्सपियर के अनेक नाटको के अलावा आइविल के अनेक अंशों तक को 'छटे लिटरेचर' की श्रेणी में रखकर प्रतिबंधित करना चाहते हैं। पर हमारी अंधी सांस्कृतिक रूप से निरक्षर जैसी असंवेदनशील पढ़े लिखों की शुतुमुर्गी दृष्टि वाली पीढ़ी देश में साम्प्रदायिकता के बीज ढूंढने में तो कुलांचे भरती है पर बारह के पाक्षपातपूर्ण विसाक्त गुणों के बारे में टिप्पणी करने में भी कतराते हैं। एक संवेदनशील व विद्वान पश्चिम लेखक को शेक्सपियर पर भी उंगली

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उठाने में कदाचित कोई भय नहीं लगता है या इस देश में उसकी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के आगे विनयवनत बुद्धिजीवियों को उनको उद्धृत करने में भी संकोच लगता है।

हरिकृष्ण निगम
ए-1002, पंचशील हसर्दट्स महावीर नगर,
कान्दिवली (9) मुम्बई-6

यह भी सच है

अमेरिका के हिन्दू संगठन को मिल मुआवजा

कैलिफोर्निया के शिक्षा बोर्ड पर मुकदमा करने वाले हिन्दू अमेरिकी माता-पिता के एक संगठन ने कोर्ट के बाहर समझौता हो जाने के बाद मामला वापस लेने का निर्णय किया है। इस संगठन ने पाठ्यपुस्तकों में हिन्दुत्व के बारे में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किये जाने का आरोप लगाते हुए बोर्ड के खिलाफ मामला दायर किया था। समझौते के बाद कैलिफोर्निया का शिक्षा विभाग और प्रांतीय शिक्षा बोर्ड कैलिफोर्निया पेरंट्स फॉर द इक्वलाइजेशन ऑफ एजूकेशन मैटेरियल्स (कापीम) को 1 लाख 75 हजार डालर का मुआवजा देने को तैयार हो गया है। संगठन ने अपने बयान में कहा- कैलिफोर्निया का शिक्षा बोर्ड मुद्दे को स्पष्ट तरीके से समझ गया है, इसलिए कापीम ने मुकदमे को और लंबा न खींचने का निर्णय किया है। प्रांत ने कापीम के साथ समझौत किया और स्वेच्छिक तौर पर मुकदमा वापस लेने के बदले कापीम को एक लाख 75 हजार का जुर्माना देने का निर्णय किया है। कापीम ने वर्ष 2006 में कैलिफोर्निया के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। संगठन ने सार्वजनिक स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में धार्मिक तथ्यों को शामिल करने की प्रक्रिया और साथ ही पाठ में धर्म के बारे में की गयी टिप्पणी को चुनौती दी थी।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शिक्षा का अधिकार

– मा. दीनानाथ बत्रा

शिक्षा के अधिकार कानून को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।

इस कानून के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं

1. 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी।

2. आठवीं कक्षा तक कोई भी बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। 14 वर्ष की आयु की अवधि में किसी भी बालक को किसी कक्षा में दूसरे वर्ष के लिए उसी कक्षा में पढ़ने के लिए बाधित नहीं किया जायेगा और न ही उसे विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

3. आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले प्रत्येक विधार्थी को प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

4. विद्यालयों में आचार्य तथा छात्र संख्या प्रतिशत निश्चित रहेगी।

5. यह कानून जम्मू काश्मीर तथा अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़ कर देश के सभी भागों में लागू होगा।

6. आर्थिक दृष्टि से लाभों से वंचित 25 प्रतिशत बालक बालिकाओं को सभी प्राईवेट विद्यालयों में प्रथम कक्षा में प्रवेश अनिवार्य रूप से मिलेगा।

7. प्रत्येक माता-पिता अथवा बालक के संरक्षक का दायित्व होगा कि वह बालकों को पड़ोस के विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश दिलायें।

8. आयु के प्रमाणपत्र न होने के स्थिति में प्रवेश के लिए कोई भी बाधा उपस्थित नहीं की जायेगी।

9. प्रशिक्षित अध्यापकों को ही विद्यालयों में पढ़ाने की अनुमति होगी।

10. अध्यापकों को आबादी की मतगणना कार्य के अतिरिक्त किसी भी कार्य में नहीं लगाया जायेगा।

11. इस बिल के कानून बनने पर क्रियान्वयन के पश्चात उचित अधिकारी की स्वीकृति अथवा मान्यता के बिना सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा विद्यालय को स्थापित नहीं करने दिया जायेगा।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

12. अध्यापकों को ट्यूशन करने के लिए मना किया गया है। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri शारीरिक दण्ड देना अपराध स्वीकार किया गया है।

इस बिल के माध्यम से चेतावनी दी गई है कि जो भी इन प्रावधानों की उलंघन करेगा उस व्यक्ति को एक लाख रुपये जुर्माना होगा।

शिक्षा के अधिकार कानून के कई प्रावधानों की आलोचना हुई है।

हैदराबाद में सहस्त्रों शिक्षाविदों ने इस कानून के विरोध में प्रर्दशन किया। कोल्हापुर (महाराष्ट्र) की 700 महिलाओं ने भी विरोध प्रकट किया। भोपाल में प्रर्दशन हुआ और रोष प्रकट किया गया।

बिल की समीक्षा :

1. उच्चतम न्यायालय ने 1993 के उन्नीकृष्णनन ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि 14 वर्ष की आयु को पूर्ण करने तक हर बालक/बालिका का नि:शुल्क तथा अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। इसमें 6 वर्ष से नीचे के विद्यार्थियों का भी समावेश किया गया है।

● 2009 के कानून के लागू होने पर 6 वर्ष से नीचे के बच्चे जिन की संख्या 17 करोड़ है उनके लिये पोषक आहार, स्वास्थ्य संरक्षण और शिशु शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित ही किया गया है।

● 19 करोड़ बच्चे जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के अन्दर आते हैं उनको शिक्षा उस ढ़ंग से प्रदान की जायेगी जैसे राज्य सरकारें उचित समझेंगी।

2. इस कानून में तीन प्रमुख न्यूनताएँ हैं।

● संविधान की धाराओं के आधार पर सभी छात्रों को समान रूप से गुणवता तथा अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कानून में निश्चितता नहीं है।

सरकारी विद्यालय धीरे-धीरे बंद हो जाएंगे। 2009 के शिक्षा का अधिकार को विशेष श्रेणी के विद्यालयों जैसे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और निजी तथा सरकार की सांझादारी से 6000 नये आदर्श विद्यालयों की स्थापना यह सब कानून की सीमा से बाहर रहेंगे। अत: बालक अच्छी शिक्षा से वंचित किये जाते रहेंगे।

● शिक्षा में निजीकरण तथा व्यापारीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इन तीन प्रमुख आपतियों के अतिरिक्त 2009 के बिल में अनेक आपतिजनक प्रावधानों की आलोचना की जा रही है।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

1. राज्य और केन्द्र के बीच फंड का बटवारा नहीं हुआ है। राज्य सरकारें चाह रही हैं कि केन्द्र ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी उठाये। वित्तिय स्पष्टता न होने से समग्रता से इस कानून के क्रियान्वयन में सन्देह उपस्थित हो रहा है।

2. 6 वर्ष के नीचे के बालक के जो प्राथमिक शिक्षा की नींव हैं उसे सुदृढ़ करने का विचार नहीं किया गया। करोड़ों बच्चें इस कानून के दायरे में नहीं रहेंगे।

3. केपीटेशन फीस तथा दान की परिभाषा तो की गई है। शुल्क के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया। प्राइवेट संस्थाओं के व्यापारीकरण में वृद्धि होगी।

4. राजकीय प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की गुणात्मक शिक्षा में असमानता तथा असंतुलन बना रहेगा।

5. संविधान की धारा 350ए जिस में बालक को मातृभाषा में पढ़ने का अधि कार दिया गया है। उसे नये कानून में यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

6. विकलांग बच्चों को कानून के प्रावधानों से बाहर रखना उनके साथ घोर अन्याय किया गया है। 75 प्रतिशत इस श्रेणी के बालक विद्यालयों में हैं नहीं।

7. माता-पिता को दायित्व दिया गया है कि वह बालकों को विद्यालय में प्रवेश दिलाएं सरकारों को इस दायित्व से मुक्त किया गया है।

8. कानून की अवहेलना पर एक लाख रुपये का दण्ड निश्चित किया गया है। यह राशि स्कूल फण्ड से अथवा विद्यार्थियों पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर दे दी जायेगी। उल्लंघनकर्ता को कोई दण्ड नहीं मिल पायेगा।

9. पड़ोसी स्कूलों को परिभाषित नहीं किया गया। 1966 में कुठारी आयोग ने पड़ोसी स्कूलों की सिफारिशों की थी। 1986 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति जिसे संसद ने स्वीकृति प्रदान की थी उसमें भी नजदीक के विद्यालयों को परिभाषित किया गया था। 1992 में इस सम्बन्ध में संशोधन हुआ था। इस सब कार्यवाही के पश्चात भी राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि वह कैसे और कहां पड़ोसी विद्यालय स्थापित करें। अस्पष्ट अवधारणा के कारण क्रियान्वयन भी अस्पष्ट दिखाई दे रहा है।

10. यह कानून गरीब बच्चों को घटिया पढ़ाई के स्तर के

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
विद्यालयों में पढ़ने को बाधित करेगा। ऊँच-नीच की खाई बढ़ जायेगी।

11. बिल में आर्थिक व्यय की सम्भावनाओं को नहीं दर्शाया गया अतः बिल के क्रियान्वयन का दायित्व कौन सम्भालेगा। इस महत्वपूर्ण बिन्दु को छोड़ दिया गया है।

12. विद्यालयों में 10 प्रतिशत पद रिक्त रखने की अनुमति है। छोटे विद्यालयों तो अधिकतर खाली ही खाली दिखाई देंगे। एकल विद्यालय तो बंद ही हो जायेंगे।

श्री सिब्बल जी ने संसद में कहा है कि यह बिल ऐतिहासिक है। शिक्षा में गुणवता, सामाजिक समरसता तथा समानता लायेगा। आलोचना की जा रही है और यह किसी सीमा तक ठीक भी है कि वर्तमान विद्यालयों की स्थिति उनके संसाधनों की ओर ध्यान दिये बिना शीघ्रता में बिल लाकर हम मछली तो पकड़ना चाहते हैं लेकिन डडू हाथ में आयेगा।

1. पहली कक्षा में 80 प्रतिशत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी 9 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर केवल 56 प्रतिशत रह जाते हैं।

2. इन में से आधे बच्चे 8 वीं कक्षा तक पहुँच पढ़ाई पूर्ण कर लेते हैं।

3. 10 प्रतिशत विद्यार्थी आगे चलकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा उतीर्ण करते हैं।

4. अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियां प्रवेश के समय 80 प्रतिशत होती हैं और वह दसवीं की परीक्षा पूर्ण करने से पहले ही विद्यालय त्याग देती हैं।

5. नेशनल सैम्पल सर्वेक्षण के आधार पर

- 30 प्रतशत विद्यालयों के ठीक भवन नहीं हैं।
- स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था लड़कियों के लिये पृथक से शौचालय नहीं हैं।
- 20 प्रतिशत विद्यालयों में केवल एक ही कमरा है। अर्थात उनमें एक ही अध्यापक है।
- 10 प्रतिशत विद्यालयों में श्याम पट भी नहीं हैं।

ऐसी स्थिति में नये कानून बनाना बेकार हो जायेंगे यदि विद्यालयों की शोचनीय स्थिति में सुधार नहीं लाया गया। अतः प्रथम वरीयता के कार्य प्रथम करें।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

 ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इतिहास की पाठ्य पुस्तके तथा भावी पीढ़ी से खिलवाड़

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा कक्षा सात तथा कक्षा बारह की इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तकों का दूसरा भाग मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में है। 'प्राचीन भारत' नामक पहले भाग की पाठ्य पुस्तकों की भांति ये पुस्तकें भी पूर्वाग्रहों से युक्त, क्रमबद्धता से विमुक्त तथा मुस्लिम यशोगान से प्रयुक्त हैं। वर्णन में अनेक स्थानों पर विरोधाभास तथा कल्पनात्मकता है।

कक्षा सात की पुस्तक में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों के उद्देश्य धन-सम्पत्ति की प्राप्ति बतलाया है (पृ.21)। परन्तु सोमनाथ मंदिर के ध्वंस में महमूद की चाह इस्लाम का नेता बन श्रेय प्राप्त करने की बतलाई है (पृ. 66)। इसी भांति लेखक ने मुस्लिम शासकों, विशेषकर मुगल बादशाहों को महिमामंडित किया है तथा इन विदेशियों से संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को कोई स्थान नहीं दिया है। उदाहरण बाबर का वर्णन है, राणा सांगा का नहीं। अकबर का वर्णन है पर हेमचन्द्र विक्रमादित्य तथा महाराणा प्रताप का वर्णन नहीं। औरंगजेब का यशोगान है पर शिवाजी का वर्णन केवल दो पंक्तियों में है, और वह भी नकारात्मक।

कक्षा बारह की इतिहास की पुस्तक में बाबर का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना बतलाया है (पृ. 140)। अकबर को मुगलों का महानतम बादशाह बतलाया (पृ. 141) क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसने अपने समय का विशाल और सबसे सुदृढ़ राज्य बनाकर उसे समृद्ध भी किया। अकबर के बाद जांहगीर, शहजहां और औरंगजेब को बहुत योग्य उत्तराधिकारी (पृ. 141) बतलाया गया है।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुगल शासन को एक 'आदर्श राज्य' बताते हुए एक दैवीय प्रकाश की भी बात की गई है तथा एक मंगोल रानी अलानकुंआ की (पृ. 149) बेतुकी कहानी भी मूल पाठ्यक्रम में दी है, जो सूर्य की किरणों से गर्भवती हो गई थी। लेखक का कथन है कि सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रख-रखाव के लिए अनुदान दिए। यहां तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट किया जाता तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किये जाते थे। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन से पता चलता है (पृ. 152)। कौन इतिहासकार विश्वास करेगा इस पर। यदि दो-चार ऐसे प्रमाण मिल भी गये तो शाहजहां तथा औरंगजेब के मंदिरों के ध्वंस के क्रूर कारनामों से इतिहास भरा पड़ा है, उसका क्या? जहांगीर की न्याय की जंजीर, जिस जंजीर का एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ, का विस्तृत वर्णन अविवेकपूर्ण है। मुगल हरम का तो वर्णन है परन्तु उसकी विस्तृत व्याख्या नहीं की गई, जो अबुल फजल तथा बाद के इतिहासकारों ने की है।

लेखक ने प्रारंभ के अध्याय में तीन विदेशी यात्रियों का वर्णन किया है। इसमें अलबरूनी (उजबेकिस्तान) इब्वनवतूता (मोरक्का) तथा बर्नियर (फ्रांस) का नाम है। प्रश्न है कि इन तीनों को ही क्यों चुना गया? अलबरूनी में उसकी जाति व्यवस्था के वर्णन को विस्तार से दिया गया, जिससे वर्गभेद का वर्णन किया जा सके। बर्नियर का वर्णन करते हुए लेखक ने अपनी मानसिकता को निम्न ढंग से तोड़-मरोड़कर पुस्तक में दर्शाया है।

फ्रांसीसी दार्शनिक मान्टेस्कयू ने उसके वृतांत का प्रयोग प्राप्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया (प्राच्य अथवा पूर्व) में शासक अपनी प्रजा के निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिसे दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी सम्पत्ति अस्तित्व में नही थी (पृ. 24)।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लेखक का मत है कि कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशिया उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया (पृ. 24-25)। वस्तुतः इतिहास की पुस्तकों में यह वैचारिक घुसपैठ अनुचित है। यह तब जब कि भारत में राजा की भूमि पर पूर्ण स्वामित्व कभी नही रहा। अतः यह प्राच्य निरंकुशवादी यूरोपिय चिन्तन को भारतीय इतिहास में जबरदस्ती लादने का प्रयत्न मात्र है। इसी कारण कार्ल मार्क्स की भी एशिया के बारे में अपरिपक्व जानकारी साबित हुई।

लेखक ने एक अध्याय को 'भक्ति और सूफी परम्पराएं' नाम दिया है। इसमें आधे से अधिक भाग में सूफियों के विचार का ही वर्णन है। अकबर और औरंगजेब को धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धालु (पृ. 47) बतलाया है। परन्तु भक्ति में शंकराचार्य, माध्वाचार्य, बल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानन्द, रैदास, सूर, तुलसी, रहीम, रसखान का या तो वर्णन ही नहीं है, यदि है भी तो एक पंक्ति से कम में।

एक अध्याय में विजयनगर साम्राज्य का वर्णन है। इसमें विजयनगर की पुरातत्व की दृष्टि से नाप-तोल अवश्य पढ़ने पर भी यह नहीं पता चलता कि इसका संस्थापक कौन था? इसकी स्थापना कैसे हुई? लेखक ने इसकी खोज 1800 में बतलाई जो वस्तुतः 1779 ई. होनी चाहिए थी। तुलुब वंश का प्रारंभ 1505 ई. से हुआ, 1503 ई. से नहीं। महाराजा कृष्णदेव राय की रायचूर की लड़ाई 1520 में हुई, 1512 में नहीं। पुस्तक में इस साम्राज्य के योजक स्वामी विद्यारण्य का नाम भी नहीं दिया गया। लेखक ने ग्रामीण समुदायों तथा पंचायतों का वर्णन इस प्रकार से किया है कि छात्रों में असन्तोष, रोष तथा उनके प्रति घृणा की भावना बढ़े। जबकि यह सर्वविदित है कि अंग्रेज शासनकाल में ये संस्थाएं अंग्रेजी राज्य व्यवस्था के लिए भारी रुकावटें थीं।

लेखक का मत है कि 'हालांकि खेती लायक जमीन की कमी न थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम दिये जाते थे, इस तरह वे गरीब रहने के लिंए मजबूर थे

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
(पृ. 110)। लेखक ने अपने विचारों को छात्रों पर थोपते हुए लिखा इनकी हालत कमोवेश वैसी ही थी जैसी कि आधुनिक भारत में दलितों की है (पृ. 110)। इसी प्रकार से इतिहासकार ने भारत की ग्राम पंचायतों को आधुनिक मुखौटे से देखते हुए उनका काल्पनिक चित्रण किया है। उसने लिखा कि फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोट-मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहार मजदूरों के लिए इसमें (पंचायत) कोई जगह होगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि वंचितों तथा महिलाओं की दशा अच्छी न थी। परन्तु इसका वर्णन सन्तुलित और तथ्यात्मक होना चाहिए। आधुनिक काल से उसे जोड़ना हास्यास्पद है।

मूल प्रश्न यह है कि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्रों को मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन से उसके व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन के विकास में क्या मिला? राजनीतिक क्षेत्र में उसे मुगलों के तथाकथित महान शासकों की जानकारी मिली परन्तु उसी काल मे राजपूतों, मराठों, सिखों, जाटों के शौर्य की वास्तविक जानकारी नहीं मिली। सामाजिक क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय तथा ग्राम पंचायतों की बर्बरता की जानकारी मिली, परन्तु सामाजिक संस्थाओं, संस्कारों, शिक्षा व्यवस्था आदि से छात्र वंचित रहे। उन्हें सूफी परम्पराओं की जानकारी मिली परन्तु भारत के अनेक संतों-भक्तों के क्रियाकलापों की जानकारी से वंचित रहे। आर्थिक दृष्टि से, जिसमें भारत बहुत समृद्ध था, कंवल अमीर-गरीब के भेद तथा भूमि पर राजा के स्वामित्व तक ही उलझ कर रह गए। क्य इस प्रकार के आधे-अधूरे, अधकचरे इतिहास से भारत राष्ट्र उन्नत होगा।

इतिहास से खिलवाड़

प्राचीन भारत और नया (अ) भारत

किसी भी राष्ट्र में प्राईमरी से विश्वविद्यालय तक पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकें अत्यन्त महत्वपूर्ण होती हैं। ये इस राष्ट्र के अतीत के गौरव तथा वर्तमान की स्थिति एवं भविष्य को दिशा प्रदान करती हैं। इनसे समाज तथा राष्ट्र के साथ आगामी पीढ़ियों का भविष्य भी

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
निर्धारित होता है। पाठ्यपुस्तकों का नवीनकरण, उनमें संशोधन तथा पुर्नरचना एक स्वाभाविक शैक्षणिक प्रक्रिया है। स्वतंत्रता के पश्चात् एन.सी.ई.आर.टी के माध्यम से चार कक्षा छह से कक्षा बारह तक के पाठ्यक्रमों को बदलने के प्रयास क्रमशः 1969, 1999, 2001 तथा 2007 में किए गए। समय-समय पर शिक्षा के नीति निर्देशकों तथा पाठ्यक्रमों की रूपरेखा को भी संशोधित तथा परिवर्तित किया गया।

लेकिन इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को देखने से यह दृष्टिगोचर होता है कि इस संदर्भ में अस्पष्ट तथा भ्रामक सरकारी शिक्षा नीति निर्देशक तत्वों का सतत् विरोध भी होता रहा है। शिक्षा बचाओ आन्दोलन, लाखों की संख्या में हस्ताक्षर अभियान, विचार गोष्ठियों के आयोजन, प्रतिनिधिमण्डल द्वारा भेंट तथा संसद में अनेक प्रश्नों की बौछार आदि- सभी प्रजातांत्रिक विधियां अपनाई गईं। अन्त में पाठ्यक्रम से आपत्तिजनक अंश हटाए गए।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी यूनेस्को के माध्यम से पाठ्यपुस्तकों के लिए दो विश्वव्यापी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। प्रथम देशों में पाठ्यक्रम इस प्रकार के हों जो विभिन्न राष्ट्रों में परस्पर शांति स्थापित करने तथा हिंसा रोकने में सहायक हों। दूसरे, उनकी जड़ें उसकी संस्कृति में हों। सन् 2005 में भारत सरकार ने भी पाठ्यक्रमों की नवीन रूपरेखा प्रसारित की। इसका आमुख लिख्त्ते हुए प्रसिद्ध विद्वान यशपाल ने इसे बच्चों की भौतिक तथा सांस्कृतिक भूमि से जुड़ी तथा रटन्त ढंग से ज्ञान संचय से दूर बतलाया (देखें नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क 2005, पृ. 3)

विचारणीय विषय है कि क्या पाठ्यक्रमों की रूपरेखा को गंभीरता से अपनया गया है? क्या ये पुस्तकें देश की संस्कृति का प्रकटीकरण करती हैं? क्या ज्ञान के वर्धन में मूल सिद्धान्त को स्पष्ट करती हैं? क्या इनसे बस्ते को बोझ कम होता है? क्या यह सन्तुलित, तथ्यपूर्ण तथा क्रमवद्ध इतिहास का उद्बोधन कराती हैं?

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम में कक्षा छह, सात, आठ तथा इसके पाश्चात कक्षा बारह में भारतीय इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया है। कक्षा छह में प्राचीन भारत तथा कक्षा बारह में पुस्तक का प्रथम भाग (कुल पृ. 150) इस सन्दर्भ में दिए गए हैं। यदि कक्षा छह की इतिहास की पुस्तक का अध्ययन करें तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। यह ज्ञान की स्पष्टता के स्थान पर भ्रम तथा सन्देह ही पैदा करती है। उदाहरण के लिए पुस्तक के पहले अध्याय को लें। इसका प्रारम्भ ही 'सम्भवत:' से होता है। इसमें 'सम्भव है', 'सामान्यत:' 'ऐसा प्रतीत होता है', 'जानकारी मिलना कठिन है', ऐसा लगता है' 'ऐसा भी हो सकता है आदि वाक्यों की भरमार है। अकेले 'संभव' शब्द कम से कम बीस बार प्रयोग में आया है। क्या इन वाक्यों से विषय की स्पष्टता होगी? पूर्व संचित ज्ञान पर जरा भी ध्यान दिए बिना, ऐसी पुरातत्व शब्दावली का प्रयोग किया गया है जो छठी कक्षा के बालक के लिए सर्वथा दुरूह तथा कठिन है।

पुस्तक के लेखक ने प्राचीन भारत के इतिहास का प्रारम्भ हड़प्पा कालीन सभ्यता से किया है तथा कुछ विशिष्ट विद्वानों के कथन के आधार पर इस सभ्यता का ध्वंस 'आक्रमण' से सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। लेखक का मानना है कि 'भारत' शब्द यहां के उत्तर-पश्चिम में ही समझा जाता है। (पृ. 4) वे एक पक्षीय विचार थोंपते हुए संस्कृत को इण्डो-यूरोपियन भाषा मानते हैं। उनके अनुसार ऋग्वेद सिन्धु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा लिखा गया (पृ. 36)। जबकि सर्वविदित है कि वेद सरस्वती नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वालें लोगों द्वारा लिखा गया (पृ. 36)। जबकि सर्वविदित है कि वेद सरस्वती नदी के तट पर लिखे गए जिनका पुस्तक में नाम तक नहीं दिया है। लेखक ने मनमाने ढंग से ग्रामीण समुदाय का वर्णन करते हुए उनके निर्णयों को पक्षपातपूर्ण बतलाया है। इसी भांति वृद्धों तथा महिलाओं की दशा का वर्णन

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

असन्तुलित ढंग से किया गया है (पृ. 56)। लिंग पूजा का वर्णन करते हुए उसे परिष्कृत पत्थर कहा गयाा है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। (देखें कक्षा बारह की पुस्तक, पृ. 31)

जहां तक सांस्कृतिक जीवन मूल्यों अथवा संस्कृति से जोड़ने की बात है, इसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। चार पुरुषार्थ, धर्म के दस लक्षण, आश्रम व्यवस्था तथा प्राचीन शिक्षा प्रणाली की कोई चर्चा नहीं है। 'वेद' या 'आर्य' का अर्थ तो दूर, उसका नाम तक भी नहीं लिया गया। वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति एवं वैदिक साहित्य का वर्णन नहीं है। कोटि-कोटि भारतीय जनमानस से जुड़े राम तथा कृष्ण अथवा रामायण तथा गीता की कहीं भी चर्चा नहीं है। चन्द्रगुप्त मौर्य जैसे राष्ट्रीय शासक, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे प्रशासक, हर्षवर्धन जैसे धार्मिक एवं उदार शासक का भी वर्णन नहीं है। 'भक्ति और सूफी परम्पराएं' खण्ड में वेदव्यास, वाल्मीकि, शंकराचार्य आदि का भी नाम तक नहीं।

उपरोक्त संक्षिप्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि लेखक ने पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्यों को छोड़ दिया। वर्णित उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति चेतना एवं श्रद्धा जगाने का कहीं जिक्र नहीं है। इतिहास के पाठ्यक्रम में विद्यार्थी के स्वाभिमान, आत्मगौरव, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीयत तथा गौरवमय अतीत की अपेक्षा की गई है। विभेदकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया गया है, जो शांति और अहिंसा के भी विपरीत हैं। पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से लगता है कि हम कोई इतिहास की पुस्तक नहीं, सामान्य ज्ञान की पुस्तक पढ़ रहे हैं।

भारत के महान पुरुष तथा वामपंथी सोच

देश के राष्ट्रीय महापुरुषों का चरित्र हनन समान्यतः सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन की नीति का एक प्रमुख अंग रहा हैं संभवतः यह उनकी विचारधारा के प्रचार-प्रसार का माध्यम है। इन दोनों साम्राज्यवादी-साम्यवादी देशों का अपने विरोधियों या प्रतिकूल वैचारिक

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
विचारकों को चुन-चुन कर खत्म करना, उनकी विविध मानसिक यातनाएं देना, उन्हें जेलों में सड़ना या उनकी हत्या करवाना एक तरीका रहा है। इसके साथ ही अपने प्रतिद्वन्दियों को पूंजीवादी, बुर्जआ, प्रतिक्रियावादी, साम्प्रादायिक, रूढ़िवादी, अप्रगतिशील आदि गालियां देना उनकी रीति-नीति रही है। भारत का वामपंथ भी इसका अपवाद नहीं है। समय-समय पर भारतीय विद्वानों तथा राष्ट्रीय महापुरुषों को भ्रामक नारों तथा मनगढ़ंत धारणाओं का शिकार बनाने के असफल प्रयत्न होते रहे हैं। इनके पीछे न तो कोई ऐतिहासिक सच्चाई है और न तर्कसंगत प्रमाण। इस दृष्टि से वामपंथियों ने शायद ही कोई समाज सुधारक या राष्ट्रीय नेता छोड़ा हो। इसकी जानकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देना उपयोगी तथा समीचीन होगा।

राजा राममोहन राय, जिन्हें भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का निर्माता तथा महान समाज सुधारक आदि माना जाता है, अनेक वामपंथी उनकी सफलताओं को 'सीमित तथा संदिग्ध' तथा उन्हें 'साम्राज्यवादी' बतलाते हैं। उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने अपार धन-सम्पत्ति बटोरी तथा शाही कुलीनों की तरह अपना सामाजिक स्तर बनाया। उनेक विचार सामन्तवादी ही नहीं बल्कि पूंजीवादी थे (अयोध्या सिंह उपाध्याय, भारत का मुक्ति संग्राम, पृ. 29) वे बुर्जुवा के पथ प्रदर्शक थे (वी.पी. ब्रोडोव, इंडियन फिलास्फी इन मार्डन टाइम्स, पृ. 144)

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अपने ही राष्ट्रीय नेताओं का चरित्र हनन करके यह राष्ट्र उन्नति कर सकेगा?

भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने 1857 के महासमर के अमर सेनानियों को भी नहीं बख्शा। इसके प्रमुख संयोजक-नाना साहेब को 'धोखेबाज', रानी झांसी को 'ढुलमुल' तथा 80 वर्ष के कुंवर सिंह को एक 'तवाहसुदा' (देखिये विपिन चन्दर, मार्डन इंडिया, 114-14) कहा। इसी भांति वामपंथियों ने भारत महान समाज सुधारकों तथा आध्यात्मिक महापुरुषों न भारत महान समाज सुधारकों तथा आध्यात्मिक

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
महापुरुषों पर मनगढ़न्त आरोप लगाए तथा मनमाने निष्कर्ष निकाले। उनके वैचारिक ढांचे में महर्षि अरविन्द, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक आदि फिट नही हो पाते। वे योगिराज अरविन्द को एक सामाजिक कल्पनाओं का कर्ता, उनके विचारों को आधारहीन तथा उनके एकात्म दर्शन तथा समाज विज्ञान को किसी भी समय कहीं भी अव्यावहारिक बतलाया (वी.पी. ब्रोडोव, पृ. 336)। स्वर्मी विवेकानन्द के विचारों में प्राचीन संस्कृति के अधिक गुणगान की कटु आलोचना की। स्वामी दयानन्द के विचारों को 20वीं शताब्दी में अलगाव तथा साम्प्रदायिकता बढ़ाने वाला बताया। लोकमान्य तिलक के व्यक्तित्व की शिवाजी और गणेशोत्सव मनाने पर तथा श्री अरविन्द की भारत को 'मां' राष्ट्र को 'धर्म' कहने पर कटु आलोचना की।

वामपंथियों की दृष्टि में न तो महात्मा गांधी ने ओर न ही पंडित नेहरु ने भारत के बुर्जवाओं का नेतृत्व किया। यदि गांधी जी नष्टप्राय: अथवा विकसित कृषकों को नेतृत्व करते थे तो पं. नेहरु नगरीय उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे (मोहित सेन, गांधीइज़म आफ्टर फ्रीडम) गांधी जी के व्यक्तित्व की तो वामपंथियों अवसर के अनुकूल घिनौने ढंग से आलोचना की। आजादी से पूर्व कभी उन्हें समझौतावादी, कभी पूंजीवादी का हितैषी, स्वतंत्रता आन्दोलन का विद्रोही, छोटे बुर्जुवाओं का नेता कहा तो आजादी के पश्चात सच्चा ट्रेड यूनियन लीडर, मानवतावादी आदि कहा। एक वामपंथी नेता ने तो गांधी जी को गांधीवाद से महान बतलाया (देखें, ई.एम.एस. नम्बूदिरीपाद, द महात्मा एण्ड हिज टाइम्स)

जहां गांधी जी के चरित्र की पहले आलोचना कीऔर बाद में प्रशंसा की वहीं पं. नेहरु की पहले प्रशंसा और बाद में अलोचना की। रूस के प्रो. आर. उल्यावास्की ने नेहरु जी को हृदय से समाजवादी, साथ ही बुर्जवा राजनीतिक दल का मुखिया बतलाया। स्वतंत्रता के

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
पश्चात नेहरु जी की 'व्यक्तिगत समाजवादी' कहकर आलोचना की। प्रो. ओ.बी. मार्टशिन ने नेहरु जी के विचारों को 'अस्थिर तथा अन-उपयुक्त (द पालिटिकल न्यूज आफ जवाहर लाल, पृ. 11) बतलाया। साथ ही उसके विचारों को रूढ़िवादी परस्पर विरोध (पृ. 79 व 82) बतलाया।

इसी भांति सुभाष चन्द्र बोस के चरित्र हनन में वामपंथियों ने कोई कसर न रखी। उल्लेखनीय यह भी है कि सुभाष को दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठाने में वामपंथियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कम्युनिस्ट महासचिव पी.सी जोशी ने उनके समर्थन में अपने पत्र 'नेशनल फ्रंट' में कई लेख तथा सम्पादकीय लिखे थे (देखें 16 अक्टूबर 1938 व 5 फरवरी 1939 के लेख) परन्तु सुभाष के जापान जाने पर तोजो का कुत्ता तथा कई भद्दी गालियों से पूर्ण कार्टून (देखें, पीपुल्स वार, आंक 8 अगस्त 1942, 13 सितम्बर व 13 सितम्बर 1942 व 21 नवम्बर 1942) भी उन्होंने छापे थे।

हां, वामपंथियों विचारकों ने भारत में मुस्लिम शासकों को महान तथा मुगल शासन को शानदार माना है। उनके अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर सत्रह बार अक्रमण किसी धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि मंदिरों से धन बटोरने के लिए किये थे। जबकि स्वयं महमूद गजनवी ने अपने को मूर्तिभंजक कहा तथा तत्कालीन मुस्लिम लेखकों ने इस कथन को बार-बार दोहराया। वामपंथियों के अनुसार बाबर एक सांस्कृतिक विरासत देने वाला, अकबर भारत का महानतम शासक तथा औरंगजेब एक जिंदा पीर था। उनके विचारों में ये सभी राष्ट्रीय शासक थे जबकि इनकी तुलना में महाराणा प्रताप, शिवाजी तथा गुरुगोविन्द सिंह अपने-अपने क्षेत्रों तक सीमित थे। वामपंथियों ने इन्हें साम्प्रदायिक इतिहास में ही स्थान दिया, राष्ट्रीय नायक नहीं माना। उनके विचार में शिवाजी एक सामान्य जमींदार से ज्यादा कुछ न थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास की विडम्बना है कि शिवाजी को **सी.बी.सी.** इतिहास की पुस्तकों से निष्कासित कर दिया गया है। कक्षा छह से कक्षा 12वीं तक इतिहास की

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकों में महाराणा प्रताप का नाम तक नहीं हैं। शिवाजी का नाम केवल कक्षा सात की पुस्तक में है, वह भी एक पंक्ति में, वह भी नकारात्मक।

विचारण प्रश्न यह है कि क्या अपने ही राष्ट्रीय नेताओं का चरित्र हनन करके राष्ट्र उन्नति कर सकेगा? क्या देश की नई पीढ़ी को बप्पा, राणा सांगा, राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविन्द सिंह, बन्दा वैरागी के जीवन पढ़ने से वंचित रखा जाएगा? क्या भारतीय इतिहास का छात्र वेद, उपनिषद, रामायण तथा महाभारत के बारे में नही जान सकेगा? क्या भक्ति आन्दोलन के नाम पर केवल सूफी सम्प्रदायों का अध्ययन करेगा तथा पुस्तक में सूर, तुलसी, रसखान, रैदास, अब्दुर्रहीम खानखाना को पढ़कर थक जाएगा? क्या क्रांतिकारियों का भारत के इतिहास में कोई स्थान नहीं है? वस्तुतः इस विषय पर गंभीर चिन्तन तथा देशव्यापी चर्चा की आवश्यकता है।

-डा. सतीश चन्द्र मित्तल

चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास की शिक्षा पाठ्यक्रम पर रांची में गोष्ठी

दिनांक 2 अगस्त 2009 को झारखण्ड, बिहार, पुणे, पं. बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा तथा सम्पूर्ण उत्तर पूर्व के प्रांतों का एक सेमिनार हुआ। मा. दत्तात्रेय जी, सह बौद्धिक प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने परिसंवाद का उद्घाटन किया। मान्यवर अतुल कोठारी जी ने कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत की। कार्यक्रम के चार सत्र थे। दो सत्रों में प्रतिभागियों ने ''चरित्र एवं व्यक्तित्व विकास'' विषय पर चर्चा की और कुछ सुझाव दिया मा. दीनानाथ बत्रा जी ने प्रश्नों का उत्तर दिया और व्यक्तित्व विकास पर अपने विचार रखें। समापन श्री अतुल कोठारी जी ने किया।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का नूतन कार्यालय प्रवेश

भारत की शिक्षा भारत से जुड़े

– सुरेश सोनी, सहसरकार्यवाह, रा.स्व. संघ

गत 7 जुलाई को नई दिल्ली में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था 'शिक्षा-संस्कृति उत्थान न्यास' के नवनिर्मित कार्यालय का प्रवेश कार्यक्रम सम्पत्र हुआ। यह कार्यालय सरस्वती विद्या मन्दिर, नारायणा विहार के द्वितीय तल पर बनकर तैयार हुआ। कार्यक्रम में न्यास के सचिव श्री दीनानाथ बत्रा द्वारा लिखित पुस्तक 'शिक्षा, परीक्षा, मूल्यांकन की त्रिवेणी' का लोकार्पण भी किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ रा.स्व.संघ के सहसरकार्यवाह श्री सुरेश सोनी द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। श्री सोनी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उपस्थित गण्यमान्यजन को संबोधित करते हुए श्री सोनी ने कहा कि कभी-कभी कुछ तात्कालिक घटनाएं हमेशा के लिए प्रेरणा दे जाती हैं। उन्होंने कहा कि महाभारत में भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच हुए तरत्कालिक संवाद के कारण हमें भगवद्गीता मिली, जो आज समाज को दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसी तरह कुछ वर्ष पूर्व इतिहास से कुछ विसंगतियां दूर करने के लिए शिक्षा बचाओ आन्दोलन समिति का गठन हुआ था। उस समय इसका गठन तात्कालिक ही था परन्तु आज इसने एक संगठन का रूप ले लिया है, जो शिक्षा के लिए विभिन्न विषयों पर चिंतन-मंथन कर रही है। शिक्षा के वर्तमान स्वरूप के बारे में श्री सोनी ने कहा कि आज की शिक्षा विशेषज्ञों का निर्माण तो कर रही है परन्तु उनका संस्कार और नैतिकता से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। इसके विपरीत हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो देश की प्रगति भी करे और अपने मूल यानी देश से भी जुड़ी रहे। उन्होंने कहा कि

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो 20वीं शताब्दी में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान सुझा सके तथा अन्य देशों को भी दिशा दे सके। उन्होंने कहा कि आज देश में शिक्षा के लिए पूर्ण स्वायत्त संस्था की आवश्यकता है। जिसमें देशभर के शिक्षाविदों को रखा जाए उसका निधारिण करें। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में लोगों को शिक्षित करने के लिए चलने वाले गुरुकुल में आवश्यकता पड़ने पर धन की व्यवस्था बाहर से भी हो जाती थी। परन्तु विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाना है इसका निर्धारण गुरुकुल के आचार्य ही किया करते थे। कार्यक्रम में शिक्षा-संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव श्री दीनानाथ बत्रा ने अपनी पुस्तक 'शिक्षा, परीक्षा, मूल्यांकन की त्रिवेणी' के बारे में कहा कि आज आचार्य, प्राचार्य, तथा विद्यार्थी तीनों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। संस्कारित करने के विभिन्न पहलुओं को पुस्तक में विस्तार से दिया गया है। न्यास के सहसचिव श्री अतुल कोठारी ने न्यास के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में न्यास के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव शर्मा उपाख्य भाई जी व रा. स्व.संघ के अ.भा.प्रचार प्रमुख श्री मनमोहन वैद्य सहित रा.स्व.संघ तथा विद्या भारती के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

–प्रतिनिधि

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्र विभाजन का षड़यंत्र

गत वर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा- 'देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।' तत्पश्चात् तत्कालीन केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने एक समाचार चैनल से कहा 'देश में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी खराब है।'

भारत में अब तक चार मुसलमान राष्ट्रपति बन चुके हैं जबकि दलितों में से मात्र एक। तीन मुसलमान उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं जबकि दलितों में मात्र एक। हिन्दू बहुल प्रान्तों में बरकतुल्लाह (राजस्थान), अब्दुल गफूर (बिहार), ए. आर. अंतुले (महाराष्ट्र) मुख्यमंत्री बन सकते हैं पर जम्मू-कश्मीर में कोई हिन्दू मुख्यमंत्री बन सकता है क्या?

सच्चर समिति का गठन मार्च 2005 में किया गया और इसने नवम्बर 2006 में आनन-फानन में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दे दी। मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक राजनीतिक स्थितियों पर इसमें संस्तुतियां हैं। इस रिपोर्ट के तथ्यों पर बिना बहस किए ज्यों स्वीकार कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि-

- मुसलमानों को सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में 'संदेह' के साथ देखा जाता है।

- पुलिस, नौकरशाही, लोक सेवा आयोंग, अस्पतालों, चिकित्सकों, स्कूल व शिक्षकों तथा यात्रियों सभी पर मुस्लिम के प्रतिभेदभाव उपेक्षा और कटुता के भाव का आरोप लगाया गया है।

- मुस्लिम महिला सार्वजनिक स्थानों पर स्वयं को असुरक्षित अनुभव करती है।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

– मुस्लिमों की सब समस्याओं का कारण मुख्यतः बहुसंख्यक समाज व शासन है।

– केन्द्र सरकार की अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर मुसलमानों व ईसाईयों पर बनुग्रहों की उदारतापूर्वक वर्षा करने की भेदभावपूर्ण नीति से इनके कथित सशक्तिकरण के स्थान पर विखण्डन का खतरा उत्पन्न हो गया है। केन्द्र सरकार के कुछ निर्णय चिंताजनक हैं-

– विश्व के 55 इस्लामिक देशों में कहीं भी हज यात्रा के लिए सब्सिडी नहीं दी जाती। परन्तु भारत में इसकी रकम बढ़ती ही जा रही है। 1998 में यह 180 करोड़ से बढ़कर 2007 में 280 करोड़ रुपये हो गई है। आन्ध्रप्रदेश ने यरुशलम की यात्रा करने वाले ईसाईयों के लिए भी इसी प्रकार की योजना प्रारम्भ कर दी है।

– भारत में मुसलमानों के पास जो वक्फ सम्पत्ति है उसका अनुमानित वर्तमान मूल्य 12 लाख करोड़ तथा वार्षिक आय 12000 करोड़ रुपये है (किन्तु यह सब्सिडी इसमें से नहीं दी जाती। आयकर देने वाले किन लोगों की गाढ़ी कमाई का यह पैसा जाता है।)

– गत दिनों मे रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने एक फरमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक अल्पसंख्यकों को ऋण देने में उदारता बरतें...। इस अभियान पर निगरानी के लिए एक मोनीटरिंग कमेटी काम करेगी। (दैनिक नवज्योति, सम्पदकीय, 4-1-2006)

परिणामतः अन्य को शिक्षा हेतु ऋण पर 12-14 प्रतिशत तथा व्यवसाय हेतु ऋण पर 15-18 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है जबकि तथाकथित अल्पसंख्कों को ये ऋण 3 प्रतिशत ब्याज पर ही मिल जाते है।

–अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय को भोपाल, पुणे किशनगंज, मुर्शिदाबाद व मुल्लपुरम् में क्षेत्रीय केंद्र खोलने हेतु 2000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। जिन राज्यों में ये केंद्र खुल रहे हैं, उन्हें इसके लिए 500 एकड़ भूमि निःशुल्क देने के लिए कहा जा रहा है।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आन्ध्रप्रदेश सरकार (जिसके मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी, ईसाई हैं) द्वारा शिक्षक संस्थाओं में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण किया गया है एवं समाज कल्याण विद्यालय में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों से 12 प्रतिशत स्थान मतांरित ईसाई, मुसलमानों के लिए निर्धारित कर दिया है।

छात्रवृत्ति	कक्षा 1 से 5			कक्षा 6 से 8			कक्षा 9 से10			कक्षा 11 से 12		
(प्रतिमाह)	छात्र	छात्रा	छात्रवासी	छात्र	छात्रा	छात्रवासी	छात्र	छात्रा	छात्रवासी	छात्र	छात्रा	छात्रवासी
1. अल्पसंख्यक	150	150	150	500	500	500	500	500	1000	935	935	840
2. एस.सी.	0	0	-	15	20	20	30	40	40	425	425	-
3. एस. टी.	0	0	-	15	20	20	30	40	40	425	425	-
4. ओ.बी.सी.	25	25	-	40	40	200	50	50	250	-	-	-
5. बी.पी.एल.	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100

तमिलनाडु सरकार, द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी) के आरक्षण में कटौती कर 7 प्रतिशत स्थानों को अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण दिया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रत्येक विभाग के बजट में से 30 प्रतिशम आवंटन मुसलमानों के लिए ही नहीं किया है बल्कि खाली पड़ी सरकारी भूमि भी उन्हें आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।

बिहार सरकार ने बाढ़ग्रस्त जिलों के मुस्लिम छात्रों के शुल्क मुक्ति दी है पर अन्य छात्रों के लिए यह प्रावधान नहीं किया है। बिहार के 10वीं उत्तीर्ण करने वाले मुस्लिम छात्र को 10,000 रुपये पुरस्कार मिलेगा।

केरल सरकार ने मदरसा के मौलवियों को पेन्शन देने का निर्णय किया है।

राजस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन मांगे गए हैं। इसमें गैर राजपत्रित स्टाम्प पर अल्पसंख्यक का शपथ-पत्र देना पर्याप्त है।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
छात्र निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं तो भी छात्रवृत्ति ले सकते हैं।

वर्तमान में भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा देय छात्रवृत्तियों का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है।

मुसलमान इस प्रकार अल्पसंख्यक के भी ले रहे हैं ओ.बी.सी. के लाभ भी ले रहे हैं।

13 अगस्त 2006 को सरकार के प्रवक्ता ने लोकसभा में बताया कि मुस्लिम प्रभाव वाले 90 जिलों और 338 शहरों में मुसलमानों के लिए विशेष विकास फण्ड का प्रावधान किया गया है।

गत दिनों प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के उद्घाटन समारोह में 15 प्रतिशत बजट मुसलमानों के लिए आवंटित किया है। वित्त मंत्री ने अर्ध सैनिक बलों में अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ाने की बात की है। बजट में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

थोक वोट के लालच में सत्ताधारी लोग सर्वोच्य न्यायालय की भी नही सुन रहे। न्यायाल की खण्डपीठ ने 8 अगस्त 2005 को कहा था। 'राजनीतिक या सामाजिक अधिकारों में कमी को आधार बनाकर भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूहों को निर्धारित करने और उसे मानने की प्रवृत्ति पांथिक हुई तो भारत जैसे बहुभाषी, बहुपांथिक देश में इसका कोई अन्त होने वाल नहीं। एक समुदाय द्वारा विशेषाधिकरों की मांग दूसरे समुदाय द्वारा विशेषाधिकारों की मांग दूसरे समुदाय को ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करेगी। जिससे परस्पर संघर्ष और झगड़े ही बढ़ेंगे।

उ.प्र. में कुछ निजी स्कूलों में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के उद्देश्य से इन स्कूलों को मदरसों में बदलने की खबरों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है राजस्थान पत्रिका 24-4-2009 पृ. 7)

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकार हर हाजी को हवाई जहाज के किराए में 28 हजार रुपये सब्सिडी के रूप में खर्च करेगी। (राजस्थान पत्रिका 24-12-2006 पृ. 12)

मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के पुलिस थानों में मुस्लिम पुलिसकर्मी, मुस्लिम अध्यापक और मुस्लिम स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त करने के निर्देश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिए हैं... यही मांग मुस्लिम लीग आजादी से पहल उठाती रही थी (दैनिक नवज्योति 7-9-2007 पृ. 1)

अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को विकास का समान लाभ देने के लिए हमें अनोखे प्रयास करने होंगे। उनका संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। मनमोहन सिंह (राजस्थान पत्रिका 11-12-2007 पृ. 13)

जामा मस्जिद के इमाम बुखारी अर्जुन सिंह से मिलकर मुसलमानों के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण का दबाव बना रहे थे। राजस्थान पत्रिका 2-10-2006, पृ. 11)

फातमी समिति की सिफरिशों के अनुरूप कक्षा एक से बारहवीं तक पुस्तकें उर्दू में तैयार होगी। मुस्लिम बहुल इलाकों में अनिवार्य रूप से उर्दू अध्यापकों की नियुक्त के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उर्दू में संचालित करने की योजना है। (राजस्थान पत्रिका 9-09-2007 पृ. 13)

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Form morning till eve,

And evening till morn,

Whatever I do,

Oh, Lord of Universe

Let that be my prayar of thee!

A

Humble Offering

at the Lotus feet

of Jagad Guru Shankra Charya

-Swami **Bharti Krishen Tirthji Maharaj**

Who has revived VM

-Dr. Nariender Puri

Vedic mathematics provides very easy, one line, mental and superfast methods alongwith magic speed cross checking system. As such Maths is a boon for all competitions. Vedic metnods are easy to understand and their variety, speed and ease brings joy in the heart and smile on the face of the students. The Vedic Maths always provides a general method which is always faster than the present system but Vedic system also provides various other methods which often work with magic speed and very frequently the students of Vedic maths class move faster than the teacher and speak out the answer as soon as the problem is written on the black board.

Prof. K.R. Wiliams of London says, "This element of choice in the Vedic System, even of innovation, together with mental approach, brings a new dimension to the study and practice of Mathematics. The variety and simplicity of methods brings fun and amusement, the mental practice leads to a more agile, alert and intelligent mind and innovation naturally follows'.

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

DEVELOPMENT OF INTEGRATED PERSONALITY

The psychologists agree that most of us have creative abilities fare beyond those we use in daily life. The problem is that we don't know how to dip into the part of the brain where most of these skills are located. Instead of allowing our minds to soar, we process information in logical, sequential computer like fashion.

The remarkable split brain studies ware conducted by Noble prize winner Rogersperry of California Institute in 1960's. Roger was able to demonstrate how each side of the human brain was responsible for a different set of functions and reactions.

According to the brain specialists, the left half of the brain, systematically collects the information, does sequential analysis and arrives at the logical conclusions and capability of intuition. this most powerful facet of human personality the intuitive faculty, unfortunately, remains undeveloped in most of us. However, we experience a shift to the right mode at one time of another without realizing it. For example, we have misplaced a common item, inspite of thinking sequentially through all the things we did earlier, we just can't remember where it is. At a later time when we are just relaxing in a lawn, the solution just rises in the mind: I had left is in the table drawer. Where did this flash of insite come from? It was generated by the brain using data supplied by the left half.

Why don't we use the right brain more often? According to Judy Haims a brain research specialist, "A Large part of the answer has to do with the attitude towards left and right brain learning. From our early days are fed an academic diet of reading writing, arithmetic and straight forward analysis. Further, Haims adds "so it is little wonder that over the years our right brain has become infact the minor hemisphere".

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Indeed history over flows with examples of people who we now believe used right brain mental procedures to achieve stardom in their field. The world famous scientist Albert Einstein described his working methods this way. "This words or the language, as they are written or spoken, do not seem to play any role in the mechanism of thought."

Can right brain thinking be taught? Yes, say the expert but the experts but in takes time and practice. With the left brain silenced the holistic right moves into action.

The Vedic Mathematics system provides us with a large number of options at is going to give the result with very little effort and in minimum time. Therefore, the very first step is to look for the pattern of the problem, which essentially involves systematic use of the right half of the brain. Then the logical computations are done by the left half. Even while computing, due to various options available, the mind is always kept alert to pick up the path of least effort. This in turn brings joy in the heart and smile on the face of the students. Therefore while practicing Vedic method human brain gets the systematic training of integrated functioning of the two halves of the brain. This according to the educational experts is very likely to result in Holistic Development of Human Personality. In this context, the feed back from the American schools, where systematic teachings of Vedic Mathematics has already been introduced is thought provoking.

The teachers report that some students who learned it last spring have become very fast in doing it, and their math ability has improved significantly.

Quotes from students:

We have several alternatives for doing problems and you can choose the easiest.

It is fun and easy, really easy! It is so interesting to see different ways of doing a problem.

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Further observations :

Look at the problems from all angles. This creates Holistic thinking.

Math is fun. The bliss occurs when the mind spontaneously find the path of least action. This is nature's functioning.

The head of Maths department from St. James School London (where they are systematically and exclusively teaching Vedic Mathematics since last & years (has informed that, "The general performance of our students in Maths is excellent and it is helping them in development of their personality. Because the Vedic Methods take proper account of how the human mind works, the calculation is done faster and leaves the mind bright and full of energy. All of us find that the effect on these boys is to make them very bright. In St. James we teach the Vedic methods first. I am quite convinced that the Vedic Maths book can be used to solve Mathematics problems of all kinds".

Some students appeared to intuitively or spontaneously see the answer without computations.

One boy shouted back an answer so quickly that the teacher asked, "How did you do it?" He said "It just flashed in my awareness". This is the working of the intuitive faculty.

As such the regular practice of the most natural, mental, easy and superfast algorithms of Vedic Maths brings and upsurge of joy and bliss and should automatically lead to the Holistic Development of the human brain. In a nutshell we can say that the Vedic Maths provides the cosmic software for the cosmic computer (the human brain) creating coherence in the brain physiology,

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Sh. Madan Lal Dhingra and M.K. Gandhi

It is being said in defense of Sir Curzon Wyllie's assassination that it is the British who are responsible for India's ruin, and that, just as the British would kill every German if Germany invaded Britain, so too it is the right of any Indian to kill any Englishman. Every Indian should reflect thoughtfully on this murder. It has done India much harm, the deputation, efforts have also received a setback. But that need not be taken into consideration. It is the ultimate result that we must think of. *Mr. Dhingra's defence is inadmissible. In my view, he has acted like a coward. All the same, one can only pity the man. He was egged on to do this act by ill-digested reading of worthless writings. His defence of himself, too, appears to have been learnt by rote. It is those who incited him this that deserve to be punished. In my view, Mr. Dhingra himself is innocent. The murder was committed in a state of intoxication. It is not merely wine or bhang that makes one drunk, a mad idea also can do so.* That was the case with Mr. Dhingra. The analogy of Germans and Englishmen is fallacious. If the Germans were to invade (Britain), the British would kill only the invaders. They would not kill every German whom they met. Moreover, they would not kill an unsuspecting German, or Germans who are guests. If I kill someone in my own house without a warning-someone who has done me no harm-I cannot but be called a coward. There is an ancient custom the Arabs that they would not kill anyone in their own house, even if the person be their enemy. They would kill him after he had left the house and after he had been given time to arm himself. Those who believe in violence would be brave men if they observe these rules when killing anyone. Otherwise, they must be looked upon as cowards. It may be said that what Mr. Dhingra did, publicly and and knowing full well that he himself would have to die, argues courage of no mean

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
order on his part. But as I have said above, men can do these things in a state of intoxicaion, and can also banish the fear of death. Whatever courage there is in this is the result of intoxication, not a quality of the man himself. A man's own courage consists in suffering deeply and over a long period. That alone is a brave act which is preceded by careful reflection. I must say that those who believe and argue that such murders may do good to India are ignorant men indeed. No act of treachery can ever profit a nation. Even should the British leave in consequence of such murderous acts, who will rule in their place? The only answer is the murders. Who will then be happy? Is the Englishman bad because he is an Englishmen? *Is it that everyone with an Indian skin is good? If that is so, we can claim no rights in South Africa, Nor should there be any angry protest against oppression by Indian princes. India can gain nothing from the rule of murdereres-no mater whether they are black or white.* Under such a rule, India will be utterly ruined and laid waste. This train of thought leads to a host of reflections, but I have no time to set them down here. I am afraid some Indians will commend this murder. I believe they will be guilty of heinous sin. We ought to abandon such fanciful ideas. More about this later. (emphasis added)

The Dhingra Case

Mr. Madanlal Dhingra's case came up for hearing today (the 23rd). We were not permitted not be present in the court. Since Mr. Dhingra did not put any defence, the case did not take much time. He only stated that he had done the deed for the good of his country, and that he did not regard it is a crime. The president judge sentenced him to death. I have already given my views about his assassination. Mr. Dhingra's statement, according to me, argues mere childishness or mental derangement. Those who incited him to this act will be called to accounted in God's court, and are also guilty in the eyes of the world.

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Schools, or shops?

SC bid to end extortions

Harried parents of school children facing arbitrary fee hikes by private unaided schools will heave a sigh of relief with the Supreme Court reaffirming that unaided schools in Delhi could raise tuition and other fees only with the prior consent of the government. The verdict, in principle, would be applicable to all such schools in India. The apex court last Friday dismissed review petitions filed by several schools against its 2004 verdict under which such schools had to obtain permission from the Director of Education for hiking the fees.

The step will go a long way in ensuring that commercialisation of educational institutions stops and there is no profiteering. What the schools that had sought a review of the 2004 verdict should have recognised in the first place was that schools are not shops where lessons are sold for money and that any move to hike the fees should be rational and reasonable, not be aimed at increasing the owners' margins. The schools will now have to maintain accounts on the principles of accounting applicable to non-business and non-profit organisations, prepare financial statements every year and file these with the education director.

In another pro-student decision, the Supreme Court has held that private unaided schools cannot charge capitation fee either. Capitation fee was another convenient device to swindle the parents, which has been held illegal. But in view of the rising input costs, the schools have been permitted to charge development fee not exceeding 15 per cent of the total annual tuition fee. Hopefully, the school owners will not take it as a licence and extract this additional charge without any real development of the school.

At the same time, the apex court has strengthened the autonomy of recognised unaided private schools and modified its 2004 order so that if more than one private school was under a single management, then surplus funds of one school could be transferred to another. Such administrative freedom is necessary for efficient management, but any attempt to fleece the parents has to be forcefully nipped.

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

SECULARISM

In modern times, it is accepted, that all Religions are equal and they should exist together. It is a matter of serious concern, that if :-

1 Nature is one 2. Humanity is one 3. GOD is one. How then Religion can be more than one, at best the paths to approach GOD can be many?

Why Religion is Necessary

According to the law of cycle every entity of this universe moves in a cycle. Due to the varieties of desires nourished during human form, the BEINGS, commit enormous crimes. Thus the BEINGS under the DIVINE LAW OF KARMA are compelled to move in number of species, die and take birth again and again. Since every death and birth is extremely painful and even human life is also not wholly full of happiness, what to say of species like a dog or a worm, therefore, considering the life full of enormous pains and sorrows, the ANCIENT THINKERS evolved a technique by practicing which the HUMAN BEING can get rid of this cycle of death and birth. This is the chief motto of Religion. To achieve this objective certain code of conduct has been framed. This code of conduct is known as Religion.

ANCIENT RELIGION

THUS according to ANCIENT RELIGION, it can be stated that Religion is the basic necessity of human life, because it protects the humanity from infinite number of pains and sorrows while jeevatman is never reborn. In order to attain this status, besides the recognition of existence of Almighty God, the practitioner must learn the fundamental laws of NATURE and practice them in his life. These laws are:- 1. Sathya. 2. Tapas. 3. Daan. And 4. Selfless duty. The recognition of Divine Constitution, that is, Law of Karma and laws. like Law of Opposites/ Complimentarily, Law of Cycle/

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Change and Law of Rebirth are the essence of Religion. Finally the supreme and the Scientific Law derived from the sum total of all material sciences such as Physics, Chemistry, Biology, Anatomy, Physiology, Biophysics, Biochemistry etc. for understanding human system i.e. MICRO and Astronomy, Astrophysics, Cosmology Quantum physics, theory of Relativity Unified Field Theory etc. for understanding the Goldy Creation i.e. MACRO know AS THE MICROCOSM, SO THE MACROCOSM imparts Religion the wholesome view and therefore is known as DHARM. This equation was then transcribed into literature in the following four statements :-

1. Tatwamasi 2. Soham 3. Ayam Atma Brahaman. and 4. Aham Brahmasmi. The ABOVE DERIVATIONS ARE WHOLLY BASED ON MATERIAL SCIENCES and lead to the search of Spiritual Science. All this total knowledge has been known as VEDIC DHARM. It is hoped, that in due course the modern Science now feeding the masses enormous worldly pleasures will come to the same conclusions as above...

Shree Sanatan Dharm

Principle of I conisation invented through GAYATRI by Rishi Vishvamitra, THE GREAT SCIENTIST of his times, moved the Vedic DHARM to Sanatan Dharm. I conisation not only simplified the prayer technique by changing from formless GOD to gods having definite forms with specific colours, but also paved the path of founding BHAKTI MAARG. Shree Sanatan Dharm is so comprehensive and vast, that HINDUS hardly need any other Religion, because by meditating on the form of Lord Vishnu, particularly the BLUE colour, it not only guarantees the material wealth and worldly pleasures to the Sadhakas, but also the Liberation from the cycle of life and death. Moreover Vedic/Sanatan Dharm has been researched through Samadhi by a large group of scientists, eighty eight thousand in number called Shaunak etc, hence it can be CATEGORISED AS THE ULTIMATE AND WORD OF GOD.

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

After the search of I conisation, the lessions were so designed so as to suit the students from nursery level (feeding sugar to Ants) and up to Ph.D. level (Patanjali Yog Sutra). Thus it assumed an extremely vast and comprehensive field of knowledge. The most remarkable point is, that every individual has been given full liberty to choose his path of prayer. Since shree Sanatan Dharm is an excellent synthesis of Science, Arts and Literature, hence some people could not understand its beauty, vastness and wholesomeness, therefore, started criticising and condemning and calling it a drama and so on. Many other lost the track of SCIENCE in the greed of BEAUTY and started fighting. A bloody battle between Vaishnvites and Shaivites for one thousand years in an example, which depicts the darkest period in the history of Shree Sanatan Dharm. Since majority of HINDU SCRIPTURES have been written in the language of symbols (Digital Teachnique), therefore even today there are many, who nourish prejudices against SCIENCE, because they think, that the word meaning of SCRIPTURES are ultimate and deny any other underlying SCIENTIFIC MEANING.

Canakya Law

This law states, that any NATION will live longer provided, it has four things in common. These are given below..

1. One Ideology. 2.One Culture. 3. One Language 4. One Religion. The law aims to keep the massestied down in a single thread and thus totally cuts down any ensuing difference of opinion. The History tells us, that millions of people have been killed due to Religious battles in the word. Even today the battles are going on, and the underlying cause is the hatred, enmity MAINLY due to Religious fanaticism. The fractured views preached to the masses by the GUIDES are basically responsible for such non-stop massacre...

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

In order to implement the basic laws of Religion in life by the practitioners Non-Violence. Associated with Love, Compassion, Forgiveness for every Being are most essential mental faculties and form the core of the Religion. Other Religions are also Dharm, but MODIFIED TO SUIT THE LOCAL CONDITIONS, FOOD HABITS, TASTE AND APTITUDE of the masses, hence do not hold the wholesome view.

Indian Scenario

Indian Constitution has recognized all Religions as equal. and has permitted every Religion to profess their views freely, even though some of them do not recognise non violence as the essential nature of Religion, yet the Political Leaders are preaching the masses the lessons of SECULARISM and UNITY IN DIVERSITY. In fact the ideology of Secularism was conceived by the Vedic Rishis to maintin love, fraternity and tolerance amongst three Communities known as 1. Shaakt. 2. Vaishnuvites and 3. Shaivites and the same was correctly applicable in this context, because each of them recognised the existence of Almighty God, fundamental laws of Nature, the laws governing the human welfare as well as the Scientific law discussed above. INDIA after political Independence, for the first time was divided in 1947 on the basis of Religion. It is a case of recent past only, when a big world power, i.e. U.S.S.R. GOT DIVIDED IN TO FOURTEEN STATES. In view of all this, the political leaders, therefore, to maintain the INTEGRITY AND SOLDARITY of the NATION should REVIEW the interpretation of SECULARISM and amend the constitution accordingly.

Solution

Since for the masses the Religion is based only on FAITH. Faith turns into faith and causes difference of opinion followed by hatred, enmity and fanaticism. Fanaticism overpowers

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
Reasoning and the masses even forego WEALTH and WORLDLY PLEASURES for the sake of HEAVENLY PLEASURE taught in their Religion. This is followed by Violence and Bloodshed. Such ensuing exigency in INDIA can be avoided provided following suggestion are implemented:-

I Since Vedic Dharm/Shree Sanatan Dharm are replete with knowledge starting from Nursery class and up to Phd. Level, therefore, to develop WHOLESOME view throughout the country, the courses should be worked out in a systematic way on the scientific pattern. THE LESSONS should be worked out under ONE CENTRAL AUTHORITY and be taught from nursery class and up to University level. This kind of systematic teaching should first be introduced in all schools run by HINDU ORGANISATIONS. RIGHT FROM NURSERY CLASS, THE TEACHING OF CHARACTER BUILDING EDUCATION MUST BE INTEGRATED WITH SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION

2As a preliminary step, the heads of all Religions with full support of Political leaders should meet with firm determination, start a dialogue (Shashtraartha) and agree to delete paragraphs, which possibly can create hatred, enmity and violence. (REFER HOLY QUARN- 4.413;5.456;10.8.69; 10.9.37; 28.66.9; etc).

3As the final step, the Heads of all States along with Religious heads and under the leadership of all world Scientists should formulate a Scientific Religion, which will naturally workout to-AS The Microcosm, So The Macrocosm, This Equation teaches the prayer technique of formless GOD discussed above. The Arya Samajis, The Nirankaris, the Radhaswais, the Brahmakumaris fall within this zone. Although for explaining their prayer techiniqueto the masses, thses prople freely use Puranic stories, but keep distance

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

from idol worship. although idol worship is the most simplified version of prayer evolved by Shree Sanatan Dharm. Similarly ISLAMM preaches worship of formless GOD and negates IDOL worship. THE LOCAL CONDITIONS, THE FOOD AVAILABLE IN THE DESERT AREA, TASTE AND APTITUDE OF THE MASSES DID NOT PERMIT EVOLUTION OF ISLAAM TO THE RICHNESS, IT EVOLVED IN INDIA. IDOL WORSHIP TECHNIQUE IS NOT ONLY THE MOST SIMPLIFIED VERSION, BUT IS AN EXCELLENT SYNTHESIS OF SCIENCE, (COLOUR AND FORM) ARTS (DRESSAND ARMAMENTS) AND LITERATURE (DESCRIPTION OF QUALITIES). THESE POINTS CAN BE SORTED OUT, PROVIDED THERE IS THE STRONG POLITICAL WILL.

TO SAVE THE INTEGRITY OF THE NATION, UNITED PRESSURE FROM ALL HINDU SAINTS AND HINDU ORGANISATIONS. IS THE DIRE NEED OF TODAY AND THE MASS AWAKENING OF HINDUS IS A MUST.

Followers of ISLAAM may continue their way of worship after deleting expressions of hatred enmity and violence. Similar dialogue should be initiated with CHRISTIANITY, BODH and JAINIS and the matter sorted out. Following books can be helpful in the attainment of this objective.

I The Vedic Dharm and modern Science. 2. Manava Dharm ka Vigyan and 3. The Way To Perfect Health.

Prayer :- OH GOD PROTECT THE WHOLE WORLD.

OM SHANTI

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Teach Team Young

By : V.S. Chaudhri, I.A.S. (retd.)

General Elections to Lok Sabha are round the corner. Political parties have come up with manifestoes covering all the possible subjects under the sun except corruption and reforms in school education. Corruption seems to be a non-issue at the national level.

Corruption is rampant everywhere. It has many manifestations ranging from scams, scandals, embezzlement, misappropriation, graft and donations for admission to schools at the primary and nursery level. 'There is not a square foot of land which is free from corruption', says T.N. Seshen, a former C.E.C. in his book 'Degereration of India'.

We talk about transparency, right to information and appointment of Lok Pal to bring about probity in public life. Not that they are unimportant but what we lose sight of is that corruption starts at the ground level and has to be checked, if we are really serious about it at the stage when the child starts taking his first step i.e. at home and in schools. Honesty has to start from the cradle. Shri A.P.J. Abdulkalam, our former President had rightly said once that only three persons could stop the eveil of corruption and they are-the mother, the father and the teacher.

Kothari Commission way back in 1966 had laid great stress on the need for moral and spiritual education. One of the recommendations of the Commission was to introduce education in moral, social and spiritual values in schools.

Many States introduced moral education as a compulsory subject in school curricula. Haryana acted on this recommendation in 1995 when I had the privilege of being the Chairman of the School Education Board. A formal

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

syllabus drawn in consultation with NCERT, SCERT, CIE, IGNOU and persons of eminence in the field of education. Books were got written for classes IV to XII and prescribed Teachers were trained. Orientation programmes were conducted by SCERT and DIETS.But alas, the efforts did not yield the desired results. Perhaps, sincerity, seriousness and commitment to the cause were lacking at all levels Also, the approach was more pedagogic and less pragmatic.

If we want to wage the war against corruption, we will have to fight if out in the class rooms. And if we have to fight it out in the schools, we will have to be practical. Merely use of words such as honesty and a casual reference to it will not serve the purpose. Illustrations will have to be very specific, clear and convincing. Why should we have to follow China, Vietnam or Indonesia in introducing anti-corruption classes? Why should we need to cite the example of foreigners when it comes to honesty? Are we lacking in instances of honesty? Are we bankrupt? No. We are not.

We can Quote quite a number of names who may be acknowledged as icons of honesty. From Mahatma Gandhi to Dr. Rajendar Parsad, Jawahar Lal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Gulzari Lal Nanda, Morariji Desai and A.P.J. Abdulkalam are only a few. The list can be enlarged with a little effort. We can pick up episodes from the lives of these people and include them in the curricula.

I would like to mention two specific instances of honesty, one which is fifty years old and the other that is very recent.

Vijay Luxmi Pundit, sister of Jawahar Lal Nehru was the President of U.N. General Assembly. She stayed at the Govt. Guest House Simla with her aides and friends for about a month. She left without making any payment, perhaps under the impression that she was a State guest. The official

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
in-charge of the Guest House reported it to the XEN who in turn brought it to the notice of the Chief Engineer. The C.E reported the matter to the Chief Minister. Shri Bhim Sen Sachar was the C.M. at that time. He wrote a D.O. letter to Pt. Nehru. The amount due from Mrs. Vijay Luxmi was about Rs. 13000/- Pt Nehru regretted the mistake of his sister, enclosed a cheque for Rs. 4500/- and said that the balance amount will be remitted by him as soon as he received the royalty of his books. See! an honest Prime Minister did not have a meager sum of Rs. 13000/- in his bank account.

A.P.J. Abdul kalam was the President of the country till a couple of a years ago. Some of his relatives came and stayed in the Rastrapati Bhawan for about a week for which he payed a sum of rupees 3,54,924/- from his personal account.

We can include such excerpts from the lives of great men in the school syllabus. More than anything else we should inculcate a practical approach to teach the children. They should be motivated not to copy or cheat in the examination. On an expermental basis examination should be conducted without invigilators. Un-manned stationary shops may run in the schools where children pick up articales of their requirement and pay for them through a box kept for the purpose. Merit certificates and medals may be given for acts of honesty. They may be asked to maintain a daily diary or practical note book to record the deeds of honesty done by them in daily life. The best deed done during the week should be narrated in the morning assembly. Merit certificates and medals may be awarded for exceptional deeds of honesty. Government may also introduce a system of Honesty Awards on the lines of the bravery awards.

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

De-stressing students

- Pradeep Kumar Singh

Of late, the burden of study has tremendously increased on students, especially at the primary and secondary level, leading to cramming-based education. In general, parents, teachers, social reformers and policy makers, all desire to improve the education system so as to reduce the excessive burden on students, avoid rote learning and pressure of examination.

The fear of failure, pressure and desire to achieve something are the natural driving forces that guide the millennium child. These are the important factors applicable in every walk of life, and must be taken in the right spirit.

In the education system, a few students learn the subject seriously to enrich their knowledge, but the majority become serious to succeed and excel in examination. It is only the examination that compels the students to learn the contents of a subject in a planned manner.

The root causes of our faulty education system need to be identified. The government schools provide education from Class I onwards with admission to students at the age of 5 years plus. This seems to be quite judicious and useful. However, in recent decades, particularly in urban areas, there has been a trend of pre-primary education (nursery, LKG, UKG, etc.) where children as young as 2 years are being admitted to schools.

All this has emerged mainly because parents want their children to excel and therefore, they make all possible efforts to admit the children to school as early as possible. Working parents find it hard to give proper attention to their children due to lack of availability of time and sending them to school is the easiest option. From the business point, some private schools also encourage pre-primary admissions.

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

When children join school at an early age, they are deprived of their childhood. At the age of 5, they are too young to bear the burden of education. It is surprising that on one hand, the parents raise a hue and cry regarding pressure of examinations on students; but on the other hand, they admit their wards to pre-primary and pre-nursery classes creating unnecessary burden at an early age.

The policy of government schools to provide education from Class I onwards (primary education), with admission to students at the age of 5 years plus, can be considered for implementation uniformly throughout the country, including private schools. This will help save the childhood of children, permit more time to parents to give attention to them, and reduce tendency of useless cramming of contents in lower classes. The poor can also afford the system of education, as they need not spend their hard earned money on unnecessary classes.

A few decades back, Hindi and the regional languages were the medium of instruction, but now English as the medium of instruction is finding favour among the masses. In our society, whether rich or poor, almost all make use of the mother tongue or the national language in their daily conversation.

A major proportion of our population belongs to villages, where English is rarely used in conversation. Under these circumstances, barring a few exceptions in metros and a few major cities, students find it difficult to understand the subject contents in English, and therefore resort to cramming.

Most of the parents also are unable to help their children and are forced to engage a tutor who often fails to fulfil the purpose. It seems to be the major cause of pressure of examination among students at least up to Class X.

Therefore, the policy of medium of instruction needs to be reviewed. Up to matriculation, Hindi or the mother tongue as the medium of instruction will serve better than English.

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

However, English should continue to be taught as a language, preferably from Class III onwards, or from an appropriate level.

In the late 90s, computer education was introduced at the primary and secondary level, especially in self-financed public schools. This has helped schools collect huge fees to enrich their financial position; and it often misleads the parents in thinking that the children are learning something extraordinary.

Parents have to shell out extra money for their children to be tech savvy. Working with computers is skill-based, and it can be developed at any stage. After developing this skill on a particular software package, it can be maintained only with continuous usage.

Moreover, computer technology is highly dynamic; most of the contents taught to the students at the lower level are likely to get changed at a later stage, thus reducing the very usefulness of computer education imparted to them. Therefore, introducing computer education at a lower level is nothing but the increase in unnecessary burden on students.

A major portion of our population resides in villages, which lack proper supply of electricity. A large number of cities also do not have regular supply of electricity. Under these circumstances, computer education cannot be implemented uniformly throughout the country, and this causes an imbalance of education between rural and urban students.

Computer education is important in the modern era and it will be better to introduce the subject in matriculation and at higher levels as an optional one. A robust and sound education system is the foundation for development of a nation.

For the education system to function satisfactorily, continuous monitoring and corrective action is very important. Factors causing excessive burden on students, cramming-based education and pressure of examination are quite important and call for a redressal.

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Don't allow foreign universities in a hurry : Joshi

After stirring a hornet's nest with his ambitious 100-day programme for education sector, HRD Minster Kapil Sibal sought of allay fears over entry of foreign education universities and said these would not be expensive institutions that would " enslave" the country. He was responding to a concerted attack led by BJP's Murli Manohar Joshi, who cautioned the Government against haste in getting foreign universities into the country and "commercialising" education.

Replying to a discussion in the Lok Sabha on demand of grants for HRD Ministry, Sibal said there was a need to change opinion on allowing foreign universities on Indian soil. He said "You will have to change your mindest. Nobody in this world can enslave India." Addressing doubts over the fee structure that foreign universities. There the Education Minister told me that they charge half the fee being charged by other universities." Sibal said foreign institutions would be allowed only in areas of interest identified by the Government.

The Minister said foreign investment would have to be allowed in the education sector. "There is a requirement of Rs 4 lakh crore in the education sector. The Government cannot raise this investment on its own. For this we have to allow private sector." he said that a special legislation- Foreign Educational Providers' Bill- would help regulate the entry of foreign universities into India.

The Ministry also stressed on the requirement of a regulatory mechanism in the education sector. "There has to be an over-arching regulatory authority which would have no political interference. This authority would decide on

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
entry barriers-financial requirements, years of experience-to allow the entry of foreign universities."

Sibal even tried to clarify his position on the much-publicised move to scrap Class X board exams. He said, "Class X result decide the career of the child. It is not the child who decides his career....I have never said that I will scrap board exams. I have said that in CBSC schools, If the school is till Class XII, then if a child has to go from Class X to XI, he should not need to take the board examination."

Earlier, several members had raised concerns over allowing foreign universities in India. Initiating the discussion, BJP leader and former HRD Mininster Murli Manohar Joshi had said, "Don't be in a hurry to fulfill you 100-day agenda. If you hurry, you won't be able to do justice to the reforms process.. don't allow foreign universities blindly. Don't commercialise education. It won't be good for us."

Asking the Government not to rush with implementation of the to rush with implementation of the Yashpal Committee recommendations on education reforms, Joshi said a look into its report revealed that it was prepared in haste, by just changing terms of reference. Referring to Nalanda and Tashila universities on the past Joshi said the education in India today too should be attractive for foreign students to come here for studies. "However, I am in no way asking you to make modern education competitive, yet inculcate cultural values and humanise it, he said.

He lashed out at UPA-I for "communalising education". Joshi said, "Your predecessor (Arjun Singh) had introduced communal elements in education and tried to please minorities by establishing schools in areas where minorities live inlarge numbers. The agenda of education reforms should not be communal."

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Supporting primary education in mother tongue, the BJP leader said the needs of every region would be different, and this needed to be catered to.

The former HRD Minister opposed the plan to scrap Class X board and said, "This is not the solution to the problem of our education system. "He said that India needed to evolve a "joyous system" of education where "students don't come under pressure". he said that before scrapping the board examinations, the Government must clarify the alternative.

The fromer HRD Minister even said that there was urgent need to keep politics out of education. He said that vice chancellor appointments have increasingly been politicised. Joshi alleged that nine people in Allahabad University's governing body were from the District Congress Committee.

V Kishore Chandra Deo (Cong.) said though he agreed with Joshi that education should lead to spiritula development, it does not mean it should be religious in nature. " Education needs some fillip at this juncture," he said, adding that though the syllabus can be standardised, the heritage and culture of a particular State should be given priority.

Supriya Sule (NCP) stressed the need to improve the English language skills of teachers in rural areas so that students get a level playing field during higher education. Sumitra Mahajan (BJP) demanded an increase in the number of Kendriya Vidyalayas in States.She said even employees of State Government now wanted their children to study in KVs.

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Prof J S Rajput, Former NCERT Director awarded UNESCO's Jan Amos Comenius Medal

Prof. J S Rajput, former Director, NCERT was awarded the prestigious Jan Amos Comenius Medal for his outstanding achievements in the fields of education research and innovation by Dr Warren Mellor, Director, UNESCO in New Delhi on 19th August, 2009. Also present on the occasion were Mr. Kreuter Charge d'Affaires, Embassy Czech Republic and Mr. Amit Khare, Joint Secretary, Ministry of Human Resource Development.

The selection of the candidates for the Medal is made by a jury consisting of the President of the International Bureau of Education (IBE) Council, the Director of the IBE, a representative of UNESCO's Education Sector and a representative of the Minister of National Education, Youth and Sport of the Czech Republic. The decisions of this jury concerning the choice of candidate are submitted to the Director General of UNESCO for approval.

The Jan Amos comenius Medal, created jointly by the Ministry of National Education, Youth and sport of the Czech Republic and the Director-General of UNESCO, in 1992, on the occasion of the 400th anniversary of the birth of Jan Amos Comenius, is intended to reward outstanding achievements carried out in field of educational devotion to education and the ideals of UNESCO demonstrated throughout an important part of one's life. As well as commemorating the spiritual heritage of Jan Amos Comenius, its principal aim is to promote and encourage new initiatives making a significant contribution to the development and renewal of educatiion.

Besides Prof. Rajput, the only other Indian to receive the AMOS COMENIUS Medal was Dr. Chitra Naik, Member (Education), Planning Commission in December, 1993.

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सहयोग राशि : तन, मन, धन
(निजी वितरण हेतु)

मातृभूमि : 23616048, 23619068

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.